www.dainikjayantnews.com
कोटद्वार, शुक्रवार
27 नवम्बर 2026
वर्ष: 49
अंक: 194 पृष्ठ: 6
मूल्य: 2.00

जयन्त

निर्भीक – निष्पक्ष – जनसरोकार

www.dainikjayantnews.com
स्थापित 1979
संस्थापक : स्व. नरेन्द्र उनियाल

डाक पंजीयन पी.ए.ओ.07-2024-26 फोन: 9412081969 email: nagendra.uniyal@gmail.com

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

पैकेट पर अब लगानी होगी चीनी, नमक और फैट की चेतावनी



नई दिल्ली, एजेंसी। पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में मौजूद हानिकारक तत्वों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने खाने-पीने की पैकेट वाली चीजों पर वॉर्निंग लेबल लगाने को कहा है। ताकि उपभोक्ताओं को यह पता चल सके कि वह जिस चीज का सेवन कर रहे हैं, उसका उनकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से कहा है कि फ्रंट-ऑफ-पैकेज न्यूट्रिशन लेबलिंग नियमों को सख्त किया जाए।

कोर्ट ने दिए ये निर्देश....

कोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि पैकेट के अगले हिस्से पर 'एडेड शुगर' और 'एडेड फैट' के बजाय 'टोटल शुगर' और 'सैचुरेटेड फैट' को नमक के साथ चिंताजनक पोषक तत्वों के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। हर निशान छह कोनों वाला होगा। उसमें संबंधित चीज की तस्वीर के साथ उसके बगल में 'हाई फैट', 'हाई शुगर' या 'हाई सॉल्ट' जैसे शब्द लिखने के निर्देश दिए गए हैं। यह उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थ खरीदते समय सही फैसला लेने और स्वस्थ खान-पान के विकल्प चुनने में मदद कर सकता है। पीठ ने आगे कहा, 'एफएसएसएआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि FoPNL में 'एडेड शुगर' और 'एडेड फैट' के बजाय 'टोटल शुगर' और 'सैचुरेटेड फैट' को 'नमक' के साथ-साथ मुख्य चिंता वाले पोषक तत्वों के रूप में माना जाए।

खाई में समाई बोलेरो, मासूम समेत दो की मौत, पांच घायल

देहरादून। कालसी क्षेत्र में हरिपुर-कोटी-मीनस मोटर मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश से विकासनगर की ओर आ रही बोलेरो गाड़ी धमोग मंदिर से पहले अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। जानकारी के अनुसार, बोलेरो में चालक सहित सात लोग सवार थे। वाहन जैसे ही धमोग मंदिर के पास पहुंचा, चालक नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी सीधे गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना की सूचना मिलते ही कालसी थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम आवश्यक बचाव उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंची। दुर्गम खाई में उतरकर टीम ने काफी मशक्कत के बाद सभी घायलों और वाहन सवारों को बाहर निकाला। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया। हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान राधिका (2 वर्ष), पुत्री डमर और नरबहादुर (56 वर्ष), पुत्र गंगा बहादुर, निवासी अछाम कटारी, नेपाल के रूप में हुई है। दुर्घटना में घायल होने वालों में वाहन चालक चमन लाल (45 वर्ष), पुत्र हर्सू, निवासी चडगांव, शिमला (हिमाचल प्रदेश), डमर (32 वर्ष), पुत्र नरबहादुर, निवासी ठकारी, जिला अछाम (नेपाल), निशा (14 वर्ष), पुत्री दिनेश, निवासी कंचनपुर, जिला अछाम (नेपाल), उर्मिला (30 वर्ष), पत्नी डमर और प्रदीप (5 वर्ष), पुत्र डमर शामिल हैं। सभी घायलों का अस्पताल में उपचार कराया गया। कालसी थाना के एसएसआई नीरज कठैत ने बताया कि बोलेरो हिमाचल प्रदेश की ओर से विकासनगर आ रही थी।

कीमत करीब 208 करोड़, यह किसी भक्त का अब तक का सबसे बड़ा दान

तिरुपति में दंपती ने चढ़ाया 121 किलो सोना



चेन्नई, एजेंसी। तिरुमला के तिरुपति मंदिर में चेन्नई के एक भक्त ने गुरुवार को 121 किलो सोने के आभूषण दान किए। इनकी कीमत करीब 208 करोड़ रुपए है। यह दान वर्धमान जैन और उनकी पत्नी राधिका जैन ने दिया है। यह दान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में हुआ।

इस दान में 9 सेट में रखे 45 जेवर और 238.2 कैरेट के हीरे शामिल हैं। इनमें श्रीवारु (भगवान वेंकटेश) का मुकुट और पद्म पादालु यानी पैरों के आभूषण भी शामिल हैं। तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर को किसी एक भक्त की ओर से दिया गया यह अब तक का सबसे बड़ा चढ़ावा है।

कंपनी में अपना हिस्सा बेचा, उसी से जेवर बनवाए

चेन्नई की कंपनी 'वारा फ्यूचर एलएलपी' के चेयरमैन वर्धमान जैन ने 121 किलो सोना दान किया। वर्धमान ने कंपनी में अपनी 60% हिस्सेदारी बेचकर 6000 करोड़ रुपए हासिल किए थे। इसी रकम में से वर्धमान ने भगवान श्री वेंकटेश्वर को यह सोना दान किया।

पहले भी कई बार दान को लेकर चर्चा में रहे

2024: चेन्नई में एक मंदिर के विस्तार के लिए 1 करोड़ रुपए का योगदान दिया।

नवंबर 2024: टीटीडी के 'अन्न प्रसादम ट्रस्ट' को 1.01 करोड़ रुपए और 'प्रणदानम ट्रस्ट' को 1.01 करोड़ रुपए दान किए।

2025: एसवी भक्ति चैनल को 5 करोड़ रुपए और गौ-संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए दान किए।

मई 2026: तिरुपति के लिए एक इलेक्ट्रिक बस दान करने की घोषणा की।

अपनों ने ठुकराया, किस्मत ने मिलाया... हिमाचल के वृद्धाश्रम में हुई दिल को छू लेने वाली शादी

गुफा में जिंदगी गुजारने वाले 75 के कन्हैया को मिली 63 साल की सबीना



बिलासपुर, (हिमाचल प्रदेश) एजेंसी। हिमाचल प्रदेश में 75 साल के दूल्हे ने 63 साल की दुल्हन से शादी रचाई। दूल्हा हिमाचल के मंडी के रहने वाले हैं, जो पत्नी की मौत के बाद इस कदर टूटे कि जंगल में गुफा में रहने लगे। हालत बिगड़ी तो एक संस्था उन्हें वृद्धाश्रम में ले आई। इसी बीच पति की मौत के बाद मानसिक हालत बिगड़ने पर पश्चिम बंगाल की सबीना भी ट्रेन पकड़कर शिमला पहुंच गई। उन्हें भी संस्था ने अपने वृद्धाश्रम में रख लिया। जहां दोनों की मुलाकात हुई और अब उन्होंने शादी कर ली। दोनों अब पति-पत्नी के रूप में नए वृद्धाश्रम में रहेंगे। यह संभव हुआ हिमाचल की मानव सेवा संस्था के संस्थापक एवं चेयरमैन प्रकाश बंसल के सहयोग से, जिन्होंने पूरे रीति-रिवाज से दोनों की शादी कराई।

पत्नी की मौत के बाद घर छोड़ जंगल में रहने लगे कन्हैया- मानव सेवा संस्था के संस्थापक एवं चेयरमैन प्रकाश बंसल ने बताया कि मंडी के रहने वाले कन्हैया लाल की पत्नी की साल 2021 में मौत हो गई। इस सदमे से वह इतने टूट गए कि घर-परिवार छोड़कर जंगल में रहने लगे। करीब 7 महीने गुफा में बिताए। 2022 में ट्रस्ट ने रेस्क्यू किया। उस दौरान उनकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ गई थी और वह जिंदगी से निराश हो चुके थे।

पहले अस्पताल पहुंचाया, फिर वृद्धाश्रम लाए- मानव सेवा ट्रस्ट की टीम को कन्हैया के गुफा में रहने की जानकारी मिली। टीम ने उन्हें वहां से रेस्क्यू किया और अस्पताल में उपचार करवाया। इसके बाद उन्हें बिलासपुर के 'अपना घर' वृद्धाश्रम लाया गया। यहां रहने, देखभाल और उपचार की सुविधा मिली। धीरे-धीरे उनकी स्थिति में सुधार होने लगा और वह सामान्य दिनचर्या में लौटने लगे।

सपा का चुनावी घोषणापत्र

युवाओं को 5000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता, वृद्ध महिलाओं को 40 हजार सालाना



लखनऊ, एजेंसी। *समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को घोषणा-पत्र जारी किया। इसमें युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने, वृद्ध महिलाओं को सालाना 40 हजार और 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को टीचर्स के बराबर वेतन देने का ऐलान किया है। इसके अलावा, गरीब परिवारों को 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा देने, बंद स्कूलों को फिर से खोलने और पुरानी पेंशन बहाल करने की दिशा में काम करने का वादा किया। अखिलेश ने कहा कि आशा, आंगनबाड़ी और ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को अच्छा वेतन दिया जाएगा। उन्हें नौकरी में पक्का करने के लिए भी काम करेंगे।*

साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संविधान दिवस पर भाजपा और संविधान बदलने की बात करने वाली शक्तियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और संविधान को बदलने की साजिश कर रहे हैं। ऐसी कोशिशों को नाकाम करने के लिए सभी संविधान समर्थक एकजुट हैं। अखिलेश ने कहा कि कुछ प्रभुत्ववादी और स्वार्थी लोग अपनी परंपरागत सत्ता बनाए रखने के लिए संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। समीक्षा और पुनर्विचार के नाम पर संविधान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ऐसी शक्तियों को संविधान विरोधी, संकीर्ण सोच वाला और विध्वंसकारी बताया। 'हमारा देश संविधान से चलेगा, मन-विधान से नहीं।' अखिलेश के मुताबिक, संविधान शोषित और वंचित वर्गों के लिए ढाल की तरह है। सभी संविधान प्रेमियों का कर्तव्य है कि वे एकजुट होकर संविधान के खिलाफ किसी भी साजिश को सफल न होने दें।

सपा के साथ सीट बंटवारे के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इमरान मसूद को दी नसीहत

बीजेपी सरकार पर भी बोला हमला

लखनऊ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। लगातार दूसरे दिन यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद सपा पर आक्रामक नजर आए। सपा के 26 सीट ऑफर करने से इमरान मसूद इतने खफा हैं कि उन्होंने आज भी कहा कि हम सपा के पार्टनर हैं या नौकर। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इमरान मसूद को नसीहत दी है। उन्होंने मसूद को कम बोलने की सलाह दी। खरगे ने कहा कि हमे बोलने से ज्यादा काम करना है। संविधान दिवस के मौके पर लखनऊ में खरगे ने कहा कि कांग्रेस ने ही बाबा साहेब को संविधान सभा में पहुंचाया और उन्हें ड्राफ्टिंग कमिटी (प्रारूप समिति) का अध्यक्ष बनाया। संविधान सभा में बाबा साहेब अंबेडकर का होना बहुत जरूरी था क्योंकि उनके बिना देश का संविधान ठीक से नहीं बन सकता था। खरगे ने कहा कि आज दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है। एक तरफ हम हैं जो संविधान के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ वे हैं जो इसका विरोध करते हैं। जो हमेशा से इसके खिलाफ रहे हैं। पिछले 12 सालों से, संविधान विरोधी सोच रखने वाले लोग लगातार संविधान को कमजोर करने का काम कर रहे हैं।

अमेरिका में तूफान से 6000 फ्लाइट्स लेट, 150 उड़ानें रद्द

ऊंची लहरों से बाढ़ का खतरा बढ़ा

वाशिंगटन। अमेरिका में थैंक्सगिविंग की छुट्टियों के बीच खराब मौसम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पूर्वी और पश्चिमी तटों पर आए तूफान के कारण बुधवार को 6000 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हुईं, जबकि करीब 150 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। सबसे ज्यादा असर पूर्वी तट पर देखने को मिल रहा है। यहां 'नॉरईस्टर' नाम का तूफान आगे बढ़ रहा है। इसके चलते न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया और आसपास के इलाकों में तेज



हवाएं और भारी बारिश होने की आशंका है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने से तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। कैलिफोर्निया समेत कई राज्यों में इससे निपटने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच मियामी एयरपोर्ट पर भारी बारिश के कारण एक मालवाहक विमान उतरते समय रनवे से आगे निकल गया। इसके बाद कुछ समय के लिए एयरपोर्ट के ज्यादातर रनवे बंद करने पड़े, जिससे विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई।

14 साल में सबसे ऊंचा जलस्तर होने का अनुमान

अमेरिका के पश्चिमी तट पर तेज लहरों के कारण समुद्र किनारे बने ढांचों को नुकसान पहुंचा है। सैन डिएगो के आसपास समुद्र का पानी पुराने रिकॉर्ड से भी ऊपर पहुंच गया। इससे आसपास के तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका के पूर्वी तट पर 2012 में आए सुपरस्टॉर्म सैंडी के बाद अब समुद्र का जलस्तर सबसे ज्यादा हो सकता है। डेलावेयर और न्यू जर्सी के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के कारण बिजली गुल होने का भी खतरा है। देश के मध्य हिस्सों में बुधवार से शुक्रवार तक बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। वहीं, पैसिफिक नॉर्थवेस्ट इलाके में बुधवार रात से बारिश और तेज हवाओं का एक और दौर शुरू होने की आशंका है।

आईआरसीटीसी घोटाला मामला

लालू परिवार को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रखा बरकरार

नई दिल्ली। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित अन्य की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। ट्रायल कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2025 को सभी के खिलाफ आरोप तय किए थे और कहा था कि प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकलता है कि लालू यादव को पूरी प्रक्रिया की जानकारी थी और उन्होंने होटलों के हस्तांतरण को प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप किया।

टेंडर प्रक्रिया में किए गए थे महत्वपूर्ण बदलाव- ट्रायल कोर्ट ने यह भी कहा था कि टेंडर प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। ऐसी प्रबल संभावना है कि बिक्री के समय जमीन के टुकड़ों का मूल्य कम करके आंका गया और बाद में वे लालू यादव के हाथों में चले गए।

संविधान दिवस पर पीएम मोदी का निशाना

ओबीसी आरक्षण में कटौती कर मुस्लिमों को देना चाहता है सबसे बड़ा विपक्षी दल

नई दिल्ली, एजेंसी। संविधान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए सबसे बड़े विपक्षी दल पर तीखा हमला बोला है। गुरुवार को लेख में पीएम मोदी ने दावा किया कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी ओबीसी आरक्षण में कटौती कर मुस्लिम आरक्षण लागू करना चाहती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के उद्देश्य से लाए गए डिलिमिटेशन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के गिरने के लिए भी एक विपक्षी दल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाओं को न्याय दिलाने से अब कोई भी ताकत नहीं रोक सकती।

आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा- प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी ओबीसी आरक्षण को कम करना चाहती है और मुस्लिम आरक्षण लाना चाहती है, जबकि संविधान निर्माता, विशेष रूप से डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर, इसके पूरी तरह खिलाफ थे।



प्रधानमंत्री मोदी ने चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए अनुच्छेद 356 के बार-बार किए गए दुरुपयोग का जिक्र करते हुए कहा कि एक पार्टी ने इसे लगभग सौ बार लागू किया था और एक पूर्व प्रधानमंत्री ने तो इस मामले में अर्धशतक ही लगा दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35 के कारण जम्मू-कश्मीर को 70 से अधिक वर्षों तक पूरा संविधान नहीं मिल पाया, और 2019 तक अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) और महिलाओं के अधिकारों को कुचला जाता रहा।

उन्होंने इस साल माओवादियों के खात्मे को विशेष रूप से सुखद बताया और कहा कि अब आदिवासी नागरिक बिना किसी डर के अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं।

नारी शक्ति को प्रधानमंत्री का आश्वासन

पीएम मोदी ने अपने लेख में कहा कि संविधान को आकार देने में मदद करने वाली असाधारण महिलाओं के योगदान को याद किए बिना हमारे संविधान की यात्रा अधूरी रहेगी। लेकिन इस साल की शुरुआत में जो कुछ हुआ, वह हमारे दिलों को शर्म से भर देने वाला है। उन्होंने कहा कि विधायी निकायों में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से लाए गए कानून को एक विपक्षी दल ने पारित नहीं होने दिया, जिससे एक बार फिर संवैधानिक मूल्यों के प्रति उसकी अनदेखी सामने आई है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया, मैं भारत की 'नारी शक्ति' को आश्वस्त करता हूं कि उन्हें न्याय दिलाने से हमें कोई भी ताकत नहीं रोक सकती।

विपक्ष बना अवरोध पक्ष

भारतीय संवैधानिक लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुख की बात है कि प्रमुख विपक्षी दल विरोध पक्ष के बजाय अवरोध पक्ष ज्यादा बन गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को यह समझना चाहिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बाधित करना संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने का विकल्प नहीं हो सकता।

संपादकीय

धामी सरकार का रिपोर्ट कार्ड

उत्तराखंड की राजनीति में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने 26 नवंबर को अपने पांच साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर चुनावी तैयारियों का संकेत दे दिया है। सरकार ने अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखते हुए यह दावा किया है कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में किए गए वादों में लगभग 70 प्रतिशत पूरे किए जा चुके हैं। जाहिर है कि यह रिपोर्ट कार्ड केवल सरकारी उपलब्धियों का दस्तावेज नही, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की राजनीतिक जमीन तैयार करने की एक महत्वपूर्ण कोशिश भी है। मुख्यमंत्री धामी ने अपने रिपोर्ट कार्ड में रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कानून व्यवस्था, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान, आधारभूत सुविधाओं और पर्यटन को प्रमुखता से सामने रखा है। सरकार के अनुसार लगभग 36 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, तीन लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी योजना से जोड़ने, समान नागरिक संहिता लागू करने और नकल विरोधी कानून जैसे कदमों को अपनी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल किया गया है। वही दिल्ली–देहरादून आर्थिक कॉरिडोर, ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना और चारधाम यात्रा में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को भी विकास के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। निश्चित रूप से इन उपलब्धियों को पूरी तरह नजरअंदाज नही किया जा सकता। उत्तराखंड जैसे भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना किसी भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। धामी सरकार ने कुछ ऐसे फैसले भी लिए हैं, जिनका राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर व्यापक प्रभाव देखने को मिला है। समान नागरिक संहिता इसका एक बड़ा उदाहरण है। किसी भी सरकार का रिपोर्ट कार्ड केवल उपलब्धियों की सूची से बेहतर नही हो सकता। उसकी वास्तविक सफलता इस बात से तय होती है कि आम आदमी के जीवन में कितना बदलाव आया है। यही वह कसौटी है जिस पर धामी सरकार को भी जनता के सवालों का सामना करना होगा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी चुनौती आज भी पलायन है। पहाड़ के अनेक गांवों में खाली होते मकान, बंद पड़े विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और रोजगार के सीमित अवसर विकास के दावों के सामने गंभीर सवाल खड़े करते हैं। सरकार ने 6500 से अधिक लोगों के गांवों में लौटने और रिवर्स माइग्रेशन में वृद्धि का दावा किया है, लेकिन क्या यह संख्या पहाड़ों से लगातार हो रहे पलायन की समस्या का स्थायी समाधान बन सकती है? इसी तरह बेरोजगारी का मुद्दा भी राजनीतिक बहस के केंद्र में रहेगा। 36 हजार सरकारी नियुक्तियां निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं, लेकिन प्रदेश में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं की अपेक्षाएं इससे कही अधिक हैं। सरकारी नौकरियों के साथ निजी क्षेत्र में रोजगार, स्थानीय उद्योगों का विस्तार और स्वरोजगार के अवसरों पर भी सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और समयबद्ध नियुक्तियां भी भविष्य में सरकार के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनेंगी।पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड ने निश्चित रूप से अपनी पहचान को व्यापक बनाया है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और प्रदेश में पर्यटकों का आगमन अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत हैं। लेकिन पर्यटन का लाभ केवल कुछ प्रमुख धार्मिक स्थलों और मैदानी क्षेत्रों तक सीमित नही रहना चाहिए। गढ़वाल और कुमाऊं के दूरस्थ पर्यटन स्थलों तक सुविधाओं का विस्तार, स्थानीय युवाओं को रोजगार और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना भी उतना ही आवश्यक है। दूसरी ओर, देहरादून सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों में यातायात का दबाव, अनियोजित निर्माण, जलभराव, प्रदूषण और लगातार सिकुड़ते प्राकृतिक संसाधन शहरी विकास की दिशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपदा की दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड में सड़क निर्माण और अन्य विकास परियोजनाओं के साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो भाजपा का यह रिपोर्ट कार्ड आगामी चुनाव की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुख्यमंत्री धामी के सामने एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल को प्रदेश की उपलब्धियों से जोड़ने की चुनौती है, वही दूसरी ओर लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का भाजपा का लक्ष्य भी है। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में किसी एक दल के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का लक्ष्य अपने आप में महत्वपूर्ण है। हालांकि विपक्ष के पास भी सरकार को घेरने के लिए अनेक मुद्दे मौजूद हैं। बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार के आरोप और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति जैसे विषय चुनावी विमर्श को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में भाजपा के लिए केवल उपलब्धियां गिनाना पर्याप्त नही होगा, बल्कि इन सवालों के ठोस जवाब भी देने होंगे।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिपोर्ट कार्ड सरकार तैयार करती है, लेकिन उसका अंतिम मूल्यांकन जनता करती है। सरकार भले ही अपने पांच साल के कामकाज को 70 प्रतिशत चुनावी वादों की पूर्ति के रूप में प्रस्तुत कर रही हो, लेकिन शेष 30 प्रतिशत वादों का हिसाब भी जनता जानना चाहेगी। उत्तराखंड की जनता भावनात्मक मुद्दों के साथ–साथ अपने दैनिक जीवन से जुड़े सवालों को भी महत्व देती है। आगामी विधानसभा चुनाव में असली मुकाबला सरकारी दावों और विपक्ष के आरोपों के बीच ही नही, बल्कि सरकार की उपलब्धियों और जनता की वास्तविक अपेक्षाओं के बीच भी होगा।अंततः धामी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी उपलब्धियों का प्रचार करना नही, बल्कि उन उपलब्धियों को जनता के अनुभव का हिस्सा बनाना है। 2027 में जनता केवल यह नही पूछेगी कि सरकार ने क्या–क्या किया, बल्कि यह भी पूछेगी कि उसके जीवन में वास्तव में कितना बदलाव आया। यही सवाल धामी सरकार के रिपोर्ट कार्ड का सबसे बड़ा परिणाम तय करेगा।

यूपी 2027 विधानसभा चुनाव: धर्म और अधर्म का युद्ध या संविधान और सत्ता की लड़ाई



सनत जैन

उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की राजनीतिक बिसात अभी से बिछने लगी है। जिस तरह के राजनीतिक और सामाजिक हालात बन रहे हैं, उन्हें देखकर महाभारत के युद्ध की याद आना स्वाभाविक है। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच सत्ता, अधिकार और धर्म की लड़ाई थी। युद्ध जीतने के लिए चक्रव्यूह रचे गए, अभिमन्यु को घेरकर मारा गया और धर्मराज युधिष्ठिर के मुख से निकले आधे-अधूरे सत्य ने युद्ध की दिशा को प्रभावित किया। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कुछ ऐसे ही दांव-पेच दिखाई देने लगे हैं। हालांकि इस तुलना को राजनीतिक घटनाओं की वास्तविक स्थिति को देखते हुए तुलना के रूप में समझना चाहिए। धर्म और दूसरे को अधर्म का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में विपक्ष मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठा रहा है। उसका आरोप है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का चुनाव आयोग पालन नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग भाजपा के पक्ष में काम कर रहा है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष विपक्ष की एकजुटता को चुनौती देने के लिए राजनीतिक रणनीतियां अपना रहा है। सवाल यह है कि क्या चुनाव जनता के वास्तविक मुद्दों पर लड़ा जाएगा या एक-दूसरे को राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए नए चक्रव्यूह एवं साजिश रची जाएंगी? उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और दलित मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी ने पीडीए बनाया है। समाजवादी पार्टी की रणनीति को चुनौती देने के लिए चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक सक्रियता उत्तर प्रदेश के चुनाव में नए समीकरण बना सकती है। मायावती की चुनावी सक्रियता भी इन समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। इन दलों और नेताओं को भाजपा की बी टीम बताने जैसे आरोप भी राजनीतिक बहस का हिस्सा हैं। ऐसे आरोपों का फैसला अंततः मतदाता अपने विवेक से करेगा। विपक्षी मतों का बंटवारा किसे लाभ पहुंचाएगा, यह इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

दूसरी ओर धार्मिक राजनीति का स्वर भी तेज होता दिखाई दे रहा है। भगवान राम और भगवान कृष्ण के नाम पर राजनीतिक और धार्मिक विमर्श के बीच बाबा रामदेव और धीरेंद्र शास्त्री के विवाद ने एक नई बहस को जन्म दिया है। धर्म के नाम पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने, साधु-संतों और बाबाओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप और वैचारिक टकराव दिखाई दे रहे हैं। राम मंदिर निर्माण, चंदे को लेकर उठे विवाद, युवाओं के असंतोष और जेन-जी से जुड़े आंदोलनों के बीच हिंदुत्व कमजोर होता हुआ दिख रहा था। समाज के भीतर अलग-अलग विचारधाराएं, अलग-अलग आस्थाएं और हिंदुओं के कई समूह सक्रिय हैं। ऐसे वातावरण में धार्मिक भावनाओं का चुनावी इस्तेमाल हिंदुत्व की सामाजिक एकता के लिए चुनौती बन सकता है। इस पूरे राजनीतिक संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष संविधान है। भारत का लोकतंत्र किसी धार्मिक ग्रंथ की व्याख्या या किसी राजनीतिक दल की इच्छा से नहीं, बल्कि संविधान और कानून से संचालित होता है। महाभारत में धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हुआ था। वर्तमान में लोकतंत्र की रक्षा, आधुनिक भारत में संविधान के अनुसार न्याय, समानता, स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकार इस लड़ाई में शामिल हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता, मतदाता के मत का सम्मान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संस्थाओं की जवाबदेही लोकतंत्र के मूल आधार हैं। 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन या सत्ता बचाने की लड़ाई नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव तय करेगा कि केंद्र में भविष्य में किसकी सरकार बनेगी। राजनीति, धर्म के नाम पर समाज को बांटेगी या संविधान के आधार पर सबको समान अधिकार देगी। लोकतंत्र में जनता ही निर्णायक होती है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को विजय तो मिली, लेकिन दोनों पक्षों ने अपनों को खोया। आज भारत को ऐसे चुनाव की जरूरत है, जिसमें जीत किसी भी दल या गठबंधन की हो लेकिन लोकतंत्र मजबूत हो। इस चुनाव में लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक सद्भाव और संवैधानिक मर्यादाओं की हार नहीं होनी चाहिए। असली धर्म सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि सत्ता का उपयोग जनकल्याण और न्याय के लिए करना है। 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव का यही लक्ष्य सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच होना चाहिए।

शीतकालीन सत्र : परिसीमन -महिला आरक्षण विधेयक से सरकार की अग्निपरीक्षा



सौरभ वार्ष्णेय

संसद का आगामी सत्र देश की राजनीति के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने मंत्रियों को 15 दिसंबर से पहले संसद सत्र की तैयारियां पूरी करने और सत्र से पहले विदेश यात्राओं से बचने की सलाह देना इस बात का संकेत है कि सरकार आगामी संसदीय कार्यवाही को लेकर बेहद गंभीर है। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री का यह निर्देश ऐसे समय आया है, जब संसद के मानसून सत्र के स्थगित होने के 100 से अधिक दिन बाद भी उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है। इस स्थिति ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। विपक्ष जहां संसद सत्र बुलाने में देरी को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष के सामने परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण विधेयक को लेकर राजनीतिक और संवैधानिक चुनौतियां खड़ी हैं।

दरअसल, संसद का सत्र केवल विधायी कार्यवाही का माध्यम नहीं होता, बल्कि यह लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष के बीच संवाद, जवाबदेही तथा राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श का सबसे महत्वपूर्ण मंच भी है। ऐसे में संसद की बैठक बुलाने और उसे समय पर संचालित करने को लेकर उठने वाले सवालों को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। संसद की कार्यवाही में निरंतरता और पारदर्शिता लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी जरूरत है।

मानसून सत्र 13 अगस्त को स्थगित हुआ था। इसके बाद से सत्रावसान नहीं होने और अगले सत्र की तारीख को लेकर अनिश्चितता ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का अवसर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर संसद की बैठक बुलाने में देरी कर रही है। हालांकि, सरकार के पास संसदीय कार्यक्रम निर्धारित करने का संवैधानिक और प्रक्रियागत अधिकार है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि संसद को राजनीतिक सुविधा के अनुसार चलाने की धारणा मजबूत होने दी जाए। संसद का महत्व किसी एक दल या सरकार से बड़ा है।

आगामी सत्र में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा परिसीमन से जुड़ा महिला आरक्षण विधेयक माना जा रहा है। सरकार यदि इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करती है तो यह उसके लिए एक बड़ी राजनीतिक और विधायी परीक्षा होगी। संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। लोकसभा की 543 सदस्यीय वर्तमान संरचना में दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा 362 सदस्यों का है, जबकि राजनीतिक चर्चाओं में 361 मतों का आंकड़ा भी सामने रखा जा रहा है। ऐसे में सरकार को अपने मौजूदा संख्याबल से आगे बढ़कर विपक्षी दलों का समर्थन जुटाना होगा।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के पास वर्तमान में लगभग 320 सांसदों का समर्थन बताया जा रहा है। इस स्थिति में सरकार के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित कराना आसान नहीं होगा। केवल गठबंधन के संख्याबल के भरोसे संसद में दो-तिहाई बहुमत हासिल करना संभव नहीं दिखता। यही कारण है कि सरकार को क्षेत्रीय दलों और विपक्ष के कुछ घटकों के साथ संवाद स्थापित करना पड़ सकता है।

यहां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या महिला आरक्षण जैसे व्यापक सामाजिक महत्व के विषय को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठाकर देखा जाएगा? महिलाओं को विधायी संस्थाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना भारतीय लोकतंत्र की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता है। लेकिन यदि इस व्यवस्था को परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़कर लागू किया जाता है तो इसके राजनीतिक, सामाजिक और संघीय प्रभावों पर गंभीर चर्चा आवश्यक हो जाती है।

परिसीमन का मुद्दा केवल लोकसभा की सीटें बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध देश के संघीय ढांचे, राज्यों के प्रतिनिधित्व और राजनीतिक संतुलन से है। विशेष रूप से दक्षिण भारत के राज्यों की चिंताएं महत्वपूर्ण हैं। इन राज्यों का तर्क है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे में यदि भविष्य में लोकसभा सीटों का निर्धारण केवल जनसंख्या के आधार पर किया जाता है तो जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों का संसद में सापेक्षिक राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है।

यह चिंता पूरी तरह नजरअंदाज नहीं की जा सकती। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक के मत का समान महत्व होना चाहिए, लेकिन भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण संघीय देश में राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संतुलन भी उतना ही आवश्यक है।सरकार द्वारा लोकसभा की कुल सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि के संभावित फॉर्मूले पर विचार इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस प्रस्ताव के तहत राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बनाए रखने और 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित हिस्सेदारी को संरक्षित रखने की संभावना पर चर्चा हो रही है। यदि ऐसा कोई फार्मूला सामने आता है तो वह दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।लेकिन इस विषय पर केवल राजनीतिक आश्वासन पर्याप्त नहीं होंगे। सरकार को स्पष्ट करना होगा कि प्रस्तावित परिसीमन से उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का संतुलन किस प्रकार बना रहेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी राज्य को जनसंख्या नियंत्रण और विकास के प्रयासों की सफलता के कारण राजनीतिक नुकसान न उठाना पड़े।

आगामी सत्र में विपक्ष मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर भी सरकार को घेर सकता है। विपक्ष चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, मतदाता सूची में संभावित गड़बडियों और निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग भी राजनीतिक विवाद का विषय बनी हुई है।हालांकि, निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और उसकी निष्पक्षता पर उठने वाले सवालों का समाधान तथ्यों, प्रक्रियाओं और संवैधानिक मर्यादाओं के आधार पर होना चाहिए। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता लोकतंत्र की विश्वसनीयता से जुड़ी हुई है। इसलिए सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि इस संस्था से जुड़े विवादों को राजनीतिक शोर-शराबे के बजाय संसदीय संवाद के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करें।

विपक्ष का यह भी कहना है कि संसद का सत्र समय पर बुलाया जाना चाहिए था। वहीं सत्ता पक्ष के लिए आवश्यक है कि वह सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब दे। लोकतंत्र में असहमति को बाधा नहीं, बल्कि व्यवस्था को मजबूत बनाने का माध्यम माना जाना चाहिए। संसद में हंगामा और कार्यवाही बाधित होना किसी भी पक्ष के हित में नहीं है।

अप्रैल में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 को आवश्यक समर्थन नहीं मिल पाने की चर्चा के बाद सरकार के सामने यह स्पष्ट चुनौती है कि वह इस बार पर्याप्त राजनीतिक सहमति कैसे बनाएगी। संविधान में संशोधन कोई सामान्य विधायी प्रक्रिया नहीं है। इसके माध्यम से देश की राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना में दीर्घकालिक परिवर्तन किए जाते हैं। इसलिए ऐसे विधेयकों पर व्यापक विचार-विमर्श और राजनीतिक सहमति अनिवार्य है।

महिला आरक्षण के पक्ष में देश के लगभग सभी राजनीतिक दल सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिबद्धता जताते रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब महिला सशक्तीकरण पर व्यापक सहमति है तो परिसीमन के प्रश्न पर राजनीतिक मतभेद इतने गहरे क्यों हैं? इसका उत्तर इस बात में छिपा है कि राजनीतिक दल महिला आरक्षण के सिद्धांत का समर्थन तो करते हैं, लेकिन उसके क्रियान्वयन से होने वाले चुनावी और क्षेत्रीय प्रभावों को लेकर उनकी अपनी आशंकाएं हैं। सरकार को चाहिए कि वह विधेयक का मसौदा सार्वजनिक विमर्श के लिए पर्याप्त स्पष्टता के साथ सामने रखे। राज्यों, क्षेत्रीय दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों और महिला संगठनों से विचार-विमर्श किया जाए। इससे न केवल विधेयक की स्वीकार्यता बढ़ेगी, बल्कि भविष्य में किसी प्रकार के संवैधानिक विवाद की आशंका भी कम होगी। आगामी संसद सत्र में महिला आरक्षण, परिसीमन, एसआईआर, चुनाव आयोग की भूमिका और विपक्ष के अन्य सवालों को लेकर तीखी बहस होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी का मंत्रियों को पहले से तैयार रहने का निर्देश इस बात का संकेत है कि सरकार इस सत्र को महत्वपूर्ण मान रही है। लेकिन सरकार की सफलता केवल विधेयक पारित कराने में नहीं, बल्कि संसद को सुचारु रूप से चलाने और लोकतांत्रिक संवाद कायम रखने में भी होनी चाहिए।

पंजाब में भाजपा-अकाली गठबंधन: सत्ता परिवर्तन की नई आहट



ललित गर्ग

अकाली दल के साथ आने से उसे पंजाब की स्थानीय सामाजिक संरचना में अधिक व्यापक पहुंच मिल सकती है। दूसरी ओर अकाली दल के लिए यह गठबंधन राजनीतिक पुनर्जीवन का अवसर है। कभी पंजाब की राजनीति की निर्णायक शक्ति रहे अकाली दल का जनाधार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से कमजोर हुआ है।

पंजाब की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का छह वर्ष बाद फिर साथ आना केवल दो राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन की वापसी नहीं है, बल्कि यह पंजाब के बदलते राजनीतिक समीकरणों की महत्वपूर्ण आहट है, इससे आम आदमी पार्टी का संकट बढ़ेगा और पंजाब के राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। गुरुनानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर घोषित यह गठबंधन 2027 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार के सामने एक मजबूत चुनौती के रूप में उभर सकता है। दोनों दलों का पुराना राजनीतिक रिश्ता, साझा शासन का अनुभव और एक-दूसरे के पूरक सामाजिक आधार इस गठबंधन को विशेष महत्व देते हैं। हालांकि चुनावी राजनीति में किसी गठबंधन की घोषणा सत्ता परिवर्तन की गारंटी नहीं होती, लेकिन इतना निश्चित है कि पंजाब में अब मुकाबला पहले की तुलना में अधिक रोचक, प्रतिस्पर्धी और त्रिकोणीय हो गया है। भाजपा और अकाली दल का संबंध राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के औपचारिक गठन से भी पुराना है। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और प्रकाश सिंह बादल के दौर में दोनों दलों ने जिस राजनीतिक साझेदारी की नींव रखी थी, वह लंबे समय तक पंजाब की राजनीति में सफल मॉडल बनी रही। अकाली दल का ग्रामीण और सिख समाज में प्रभाव तथा भाजपा का शहरी हिंदू, व्यापारी और मध्यवर्गीय आधार एक-दूसरे के पूरक रहे। इसी सामाजिक और राजनीतिक समीकरण के कारण दोनों दलों ने मिलकर पंजाब में कई बार सत्ता हासिल की। लेकिन 2020 में तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों के व्यापक आंदोलन के बीच यह रिश्ता टूट गया। अकाली दल ने भाजपा से दूरी बनाई और हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उस समय यह निर्णय किसानों की भावनाओं और पंजाब की राजनीतिक परिस्थितियों के दबाव में लिया गया था, लेकिन बाद के चुनावों ने यह भी दिखाया कि इस अलगाव की राजनीतिक कीमत दोनों दलों को चुकानी पड़ी।

2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर पंजाब की सत्ता पर शानदार ढंग से कब्जा किया। दूसरी ओर अकाली दल तीन और भाजपा केवल दो सीटों तक सिमट गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दोनों दल अलग-अलग मैदान में उतरे। कांग्रेस ने सात, आम आदमी पार्टी ने तीन और अकाली दल ने एक सीट जीती, जबकि भाजपा एक भी सीट नहीं जीत सकी। हालांकि भाजपा का मत प्रतिशत करीब 18.6 प्रतिशत रहा और अकाली दल को भी लगभग 13.5 प्रतिशत वोट मिले। इससे स्पष्ट हुआ कि दोनों दलों के पास अलग-अलग पर्याप्त



राजनीतिक आधार है, लेकिन अलग-अलग लड़ने पर वह वोट प्रभावी सीटों में परिवर्तित नहीं हो पा रहा है। अब छह वर्ष बाद दोनों दलों ने अपने अनुभवों से सबक लेते हुए फिर साथ आने का फैसला किया है। इसे राजनीतिक भूल-सुधार भी कहा जा सकता है और बदली परिस्थितियों की व्यावहारिक स्वीकृति भी। इस गठबंधन का सबसे बड़ा प्रभाव आम आदमी पार्टी पर पड़ना स्वाभाविक है। 2022 में आप को सबसे बड़ा लाभ विपक्ष के बिखरे होने से मिला था। कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा अलग-अलग चुनाव लड़ रहे थे और सत्ता विरोधी मत एकजुट विकल्प में परिवर्तित नहीं हो पाए। अब भाजपा और अकाली दल के साथ आने से यह समीकरण बदल गया है। भाजपा का शहरी और मध्यवर्गीय आधार तथा अकाली दल का ग्रामीण संगठन और पारंपरिक जनसंपर्क यदि प्रभावी ढंग से एक-दूसरे के पक्ष में वोट ट्रांसफर कर पाते हैं, तो आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित रूप से चुनौती बढ़ेगी। यही कारण है कि इस गठबंधन को पंजाब की वर्तमान सरकार के लिए गंभीर राजनीतिक खतरे की शुरुआत माना जा सकता है।

भाजपा के लिए भी यह गठबंधन रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पंजाब में उसने अपना मत प्रतिशत बढ़ाया है, लेकिन उसे सीटों में बदलने में कठिनाई रही है। अकेले चुनाव लड़कर व्यापक ग्रामीण और सिख सामाजिक आधार तक पहुंच बनाना उसके लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। अकाली दल के साथ आने से उसे पंजाब की स्थानीय सामाजिक संरचना में अधिक व्यापक पहुंच मिल सकती है। दूसरी ओर अकाली दल के लिए यह गठबंधन राजनीतिक पुनर्जीवन का अवसर है। कभी पंजाब की राजनीति की निर्णायक शक्ति रहे अकाली दल का जनाधार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से कमजोर हुआ है। भाजपा के साथ लौटना उसके लिए केवल सत्ता में वापसी की कोशिश नहीं, बल्कि संगठन और कार्यकर्ताओं में नया विश्वास पैदा करने का अवसर भी है। फिर भी इस गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती विश्वसनीयता की है। छह वर्ष पहले जिस कृषि कानून मुद्दे पर दोनों दल अलग हुए थे, अब उसी रिश्ते को पुनर्जीवित करने पर स्वाभाविक सवाल उठेंगे। अकाली दल को अपने मतदाताओं को समझाना होगा कि परिस्थितियां क्यों बदलीं और आज भाजपा के साथ आने का आधार क्या है। भाजपा को भी किसानों के साथ संवाद की नई और भरोसेमंद भाषा विकसित करनी होगी। लोकतंत्र में गठबंधन बनाना राजनीतिक दलों का अधिकार है, लेकिन जनता के विश्वास का सम्मान करना उनकी जिम्मेदारी भी है। विचारधारात्मक मतभेदों के बावजूद साथ आना अपने आप में अवसरवाद नहीं है, समस्या तब होती है जब राजनीतिक दल अपने पुराने रुख और वर्तमान निर्णय के बीच कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं दे पाते।

पश्चिम बंगाल और दिल्ली के राजनीतिक अनुभवों की पृष्ठभूमि में पंजाब का घटनाक्रम भाजपा की रणनीति को समझने का एक अवसर देता है। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने लंबे समय से मजबूत राजनीतिक आधार रखने वाली शक्तियों के बीच अपनी जगह बनाई और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मजबूत सत्ता को चुनौती देकर सत्ता हासिल की। पंजाब में परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन भाजपा अब यहां भी संगठन, गठबंधन और सामाजिक समीकरणों के माध्यम से सत्ता की संभावना तलाश रही है। अकाली दल का साथ इस रणनीति को स्थानीय आधार दे सकता है। लेकिन पंजाब की जनता केवल राजनीतिक गणित से प्रभावित नहीं होगी। किसान, युवा, रोजगार, नशा, उद्योग, कानून-व्यवस्था, शिक्षा और राज्य की आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दे चुनाव का वास्तविक आधार बनेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा-अकाली गठबंधन को कागज पर वोट जोड़ने से आगे बढ़कर जमीन पर कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को जोड़ना होगा। छह वर्ष तक अलग रहने के बाद दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच पैदा हुई दूरी को समाप्त करना आसान नहीं होगा। नेतृत्व का समझौता हो जाना पर्याप्त नहीं है, बूथ स्तर तक राजनीतिक सहयोग और आपसी विश्वास जरूरी होगा। यदि भाजपा कार्यकर्ता अकाली उम्मीदवार के लिए और अकाली कार्यकर्ता भाजपा उम्मीदवार के लिए पूरी निष्ठा से काम करते हैं, तभी गठबंधन की वास्तविक शक्ति सामने आएगी।

पंजाब में अब चुनावी मुकाबला केवल सरकार बनाम विपक्ष नहीं रह गया है। यह आम आदमी पार्टी के शासन के मूल्यांकन, कांग्रेस की वापसी की कोशिश और भाजपा-अकाली गठबंधन की नई राजनीतिक संभावनाओं के बीच त्रिकोणात्मक मुकाबला होगा। भाजपा-अकाली गठबंधन निश्चित रूप से आप के लिए खतरे की घंटी है, लेकिन इसे सत्ता परिवर्तन की गारंटी मानना भी उचित नहीं होगा। अंततः चुनावी निर्णय जनता के प्रदर्शन और विश्वास पर निर्भर करेगा। यदि आप सरकार जनता के बीच अपना भरोसा बनाए रखती है तो गठबंधन की चुनौती सीमित रह सकती है, लेकिन यदि सत्ता विरोधी भावना मजबूत हुई तो भाजपा-अकाली गठबंधन उस भावना को एक संगठित राजनीतिक विकल्प दे सकता है। इस गठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि क्या भाजपा और अकाली दल केवल सत्ता पाने के लिए फिर साथ आए हैं या पंजाब के लिए कोई साझा भविष्य-दृष्टि भी रखते हैं। यदि वे किसानों के सम्मान, युवाओं के रोजगार, नशामुक्त पंजाब, उद्योग के विकास, कानून-व्यवस्था और हिंदू-सिख भाईचारे को अपने साझा एजेंडे का केंद्र बनाते हैं तो यह गठबंधन केवल चुनावी समझौता नहीं, पंजाब की राजनीति में नई धुरी बन सकता है। 2020 का अलगाव, 2022 की हार और 2024 का अलग-अलग चुनाव दोनों दलों को यह सिखा चुका है कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन साझा राजनीतिक जमीन को पूरी तरह खो देना किसी के हित में नहीं। अब 2027 बताएगा कि यह पुनर्मिलन केवल सत्ता की मजबूरी है या वास्तव में पंजाब की राजनीति में एक नई शुरुआत एवं शुभ भविष्य की आहट है। गठबंधन का हाथ नेताओं ने मिलाया है, लेकिन उसकी सफलता का फैसला पंजाब की ज

गुलदार की धमक, दहशत में वार्डवासी

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : जंगल से सटे आबादी क्षेत्रों में अब दिन का उजाला भी लोगों को सुरक्षा का भरोसा नहीं दे पा रहा है।

घरों के आसपास गुलदार की चहलकदमी और उसकी दहाड़ ने लोगों के भीतर खौफ पैदा कर दिया है। भाबर क्षेत्र के पदमपुर मोटाढांक में स्थिति यह है कि स्थानीय निवासियों के मुताबिक, तीन से चार गुलदार क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं। कभी घरों के आंगन के नजदीक तो कभी बगीचों में उनकी मौजूदगी दिखाई दे रही है। गुलदार की बढ़ती सक्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लोग शाम होने का इंतजार किए बिना ही घरों में कैद होने को मजबूर हैं। बच्चों को अकेले बाहर भेजने से भी परिजन कतरा रहे हैं।


आबादी क्षेत्र का निरीक्षण करते वन कर्मी व अन्य

नगर निगम के वार्ड संख्या 31 का एक हिस्सा बिजनौर वन प्रभाग के जंगल से सटा हुआ है। यही वजह है कि क्षेत्र में हाथियों और गुलदार की आवाजाही बनी रहती है। हालांकि, पिछले कुछ दिनों से गुलदार की सक्रियता ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वार्डवासियों का कहना है कि दिन-दहाड़े गुलदार बगीचों और आबादी से लगे जंगल में घूमते नजर आ रहे हैं। कई बार उनकी दहाड़ भी सुनाई देती है। गुलदार पालतू पशुओं को भी निवाला बना रहे हैं। ऐसे में लोगों को बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा की चिंता सता रही है। क्षेत्रवासियों ने वन विभाग से गुलदार की सक्रियता पर अंकुश लगाने और नियमित गश्त की मांग की है। शिकायत के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने रात्रि गश्त बढ़ाने और समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया है।

अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी, अतिक्रमण स्वयं हटाने के आदेश

श्रीनगर गढ़वाल : राष्ट्रीय राजमार्ग को अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में एनएच डिवीजन श्रीनगर ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत कलियासौड़ स्थित धारी देवी मंदिर के ऊपर राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे से दस अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं। विभाग ने संबंधित अतिक्रमणकारियों को प्रथम चरण में नोटिस जारी कर दिए हैं। नोटिस के माध्यम से अतिक्रमण स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्धारित समयावधि में अतिक्रमण नही हटाए जाने पर विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। एनएच डिवीजन श्रीनगर की सहायक अभियंता गर्विता पांडे ने बताया कि धारी देवी मंदिर के ऊपर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दस अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं। विभाग की ओर से सभी संबंधित लोगों को पहला नोटिस जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रथम नोटिस के बाद दो और नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके बावजूद यदि संबंधित लोग निर्धारित समयावधि में अतिक्रमण नही हटाते हैं तो विभाग की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

खाली प्लाटों में उगी झाड़ियों में छिप रहे जंगली जानवर

पार्षद सौरभ नौडियाल ने नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, प्लाटों को चिह्नित कर सफाई करवाने की मांग

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : नगर निगम क्षेत्र में खाली पड़े प्लाटों में उगी झाड़ियों अब लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बनती जा रही हैं। जंगल से सटे आबादी क्षेत्रों में जंगली जानवरों की लगातार आवाजाही के बीच ये झाड़ियां उनके छिपने का ठिकाना बन रही हैं। ऐसे में आबादी के बीच वन्यजीवों की मौजूदगी से किसी अप्रिय घटना की आशंका बनी हुई है। इस समस्या को लेकर पार्षद सौरभ नौडियाल ने नगर निगम प्रशासन से खाली प्लाटों की सफाई करवाने की मांग उठाई है।

इस संबंध में नगर आयुक्त पीएल शाह को सौंपे ज्ञापन में उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में खाली पड़े प्लाटों को चिह्नित कर उनकी सूची तैयार की जाए। साथ ही संबंधित भू-स्वामियों को प्लाटों में उगी झाड़ियों की सफाई करवाने के लिए नोटिस जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि यदि भू-स्वामी स्वयं झाड़ियों की कटाई करवाने में असमर्थ हैं तो नगर निगम उनकी सफाई की व्यवस्था करे और इस पर आने वाला खर्च संबंधित भू-स्वामी से वसूल किया जाए। सौरभ नौडियाल ने कहा कि वर्तमान में नगर निगम क्षेत्र के जंगल से सटे इलाकों में जंगली जानवरों की आवाजाही बनी हुई है। ऐसे में वन्यजीव आबादी में पहुंचकर खाली प्लाटों में उगी झाड़ियों में छिप रहे हैं। इससे स्थानीय निवासियों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने नगर निगम प्रशासन से जनहित को देखते हुए खाली प्लाटों की सफाई के लिए जल्द प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की।



आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 140 रुपये बढ़ोत्तरी की मांग

सहायिकाओं का मानदेय भी 40 रुपये प्रतिदिन बढ़ाने की मांग, तहसील परिसर में दिया धरना


कोटद्वार तहसील परिसर में मांगों को लेकर धरना देती आंगनबाड़ी कार्यकर्ता।

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : महंगाई के दौर में सीमित मानदेय पर काम कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अब अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि विभागीय जिम्मेदारियों का लगातार बोझ बढ़ रहा है, लेकिन इसके अनुरूप उन्हें मानदेय नहीं मिल रहा है। ऐसे में परिवार का भरण-पोषण करने से लेकर बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाना भी मुश्किल हो रहा है। इसी समस्या को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठन से जुड़ी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को तहसील परिसर में धरना दिया और प्रदेश सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग की।

तहसील परिसर स्थित धरना स्थल पर आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे लंबे समय से अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं, लेकिन शासन-प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कई तरह के कार्य लिए जाते हैं, लेकिन इसके एवज में मिलने वाला मानदेय उनकी जरूरतों के अनुरूप नहीं है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कम मानदेय के कारण उन्हें परिवार का भरण-पोषण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाना भी चुनौती बन गया है। उन्होंने सरकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में प्रतिदिन 140 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में प्रतिदिन 40 रुपये की अतिरिक्त बढ़ोत्तरी करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर रेखा असवाल, रिंकी देवी, सीमा देवी, हेमलता देवी, रोशनी ध्यानी, रेखा नेगी, सरिता देवी, विजय लक्ष्मी और विनीता देवी मौजूद रहीं।

365 दिन रोजगार और डीए की मांग को लेकर पीआरडी जवानों ने दिया धरना

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : प्रदेश के विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे पीआरडी जवानों ने नियमित रोजगार और वेतन संबंधी सुविधाओं की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। जवानों का कहना है कि उनसे पुलिस कर्मियों की तरह जोखिम भरे और महत्वपूर्ण कार्य करवाए जा रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर उन्हें न्यूनतम मानदेय तक सीमित रखा गया है। रोजगार की अनिश्चितता और आर्थिक असमानता से नाराज पीआरडी जवानों ने तहसील परिसर में धरना देकर शासन-प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया।

प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन के ब्लाक अध्यक्ष दिनेश कुमार और सलाहकार दर्शन सिंह के नेतृत्व में विभिन्न विभागों में कार्यरत पीआरडी जवान तहसील परिसर में एकत्र हुए। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की।


कोटद्वार तहसील परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर धरना देते पीआरडी जवान।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पीआरडी जवानों से पुलिस की भांति जोखिम भरे कार्य करवाए जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न सरकारी विभागों में भी उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके बावजूद मानदेय और अन्य सुविधाओं के मामले में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जवानों का कहना था कि सीमित दिनों का रोजगार मिलने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट बना रहता है। उन्होंने प्रदेश सरकार से सभी पीआरडी जवानों को वर्षभर यानी 365 दिन रोजगार उपलब्ध कराने और होमगार्ड की तर्ज पर मूल वेतन पर महंगाई भत्ता (डीए) देने की मांग की। साथ ही कहा कि लंबे समय से सेवाएं दे रहे जवानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाना चाहिए। धरना देने वालों में हरीश चंद्र, सुनील कुमार, पपेंद्र कुमार, कुलदीप कुमार, विजय पंत, विरेंद्र प्रसाद, मनोज भट्ट, राकेश सिंह, रवि कुमार, जितेंद्र गुप्ता, राकेश जुयाल, पंकज कुमार और राजेश कुमार सहित बड़ी संख्या में पीआरडी जवान मौजूद रहे।



श्री सतपाल महाराज, मा0 मंत्री लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, सिचांई, लघु सिंचाई, संस्कृति, ग्रामीण निर्माण, बाढ़ नियंत्रण एवं भारत-नेपाल नदी परियोजनायें उत्तराखण्ड सरकार का विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण एवं भ्रमण कार्यक्रम



दिनांक 28 नवम्बर 2026 (गुरूवार)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	स्थान	समय
1	विकास खण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत डीब बैण्ड से किमोली मोटर मार्ग (स्वीकृत लम्बाई 1.100 किमी0) का डामरीकरण कार्य का लोकार्पण। लागत- 6690 लाख।	ग्राम गोलीं के निकट धामलू के शिव मन्दिर प्रांगण, एकेश्वर।	समयः 14:30
2	पाटीसैंण तछवाड़ मोटर मार्ग का (स्वीकृत लम्बाई 2.400 किमी0) सुधारीकरण/डामरीकरणकार्य का लोकार्पण। लागत- 189.70 लाख		
3	भंडारी गांव-मोन्दाड़ी-पर्याण मोटर मार्ग (स्वीकृत लम्बाई 4.000 किमी0) का शिलान्यास। लागत-505.58 लाख		

दिनांक 01 दिसम्बर 2026 (मंगलवार)

क्र0सं0	कार्य का नाम	स्थान	समय
1	विकास खण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कॉलेज किमगड़ी के कक्षा-कक्षों के नव निर्माण कार्य का शिलान्यास। लागत-155.63	राजकीय इण्टर कॉलेज किमगड़ी, विकास खण्ड पोखड़ा।	समयः 10:15
2	विकास खण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत तहसील चौबट्टाखाल के आवासीय भवन टाईप-04 (01 यूनिट) एवं अनावासीय भवन के अवशेष निर्माण कार्य का लोकार्पण। लागत- 84.84 लाख।		
3	विकास खण्ड पोखड़ा में कमलपुर इण्टर कॉलेज से संगलाकोटी झूलापुल तक मोटर मार्ग में सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य का लोकार्पण। लागत-70.43 लाख		
4	विकास खण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत रीठाखाल-पंचवटी-नाई मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनः निर्माण एवं नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण। लागत- 237.31 लाख		
5	विकास खण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत पणखेत-लटीबौ मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं क्षतिग्रस्त दीवारों के निर्माण कार्य का लोकार्पण। लागत- 31.48 लाख	जनता इण्टर कॉलेज देवराजखाल, विकास खण्ड पोखड़ा।	समयः 11:04
6	विकास खण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत बिजोरापानी से घण्डियाल तल्ला मोटर मार्ग के सुधारीकरण कार्य का शिलान्यास। लागत- 52.44 लाख		
7	विकास खण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत नाई-घस्मानी मोटर मार्ग में सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य का शिलान्यास। लागत- 77.05 लाख		

दिनांक 03 दिसम्बर 2026 (गुरूवार)

क्र0सं0	कार्य का नाम	स्थान	समय
1	विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कॉलेज भरोलीखाल में विद्यालय भवन का शिलान्यास। लागत- 175.71 लाख	राजकीय इण्टर कॉलेज भरोलीखाल, विकासखण्ड बीरोंखाल।	समय-10:40
3	विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत राजकीय डिग्री कॉलेज वेदीखाल में महिला छात्रावास भवन का लोकार्पण लागत- 358.14 लाख	राजकीय डिग्री कॉलेज वेदीखाल, विकास खण्ड बीरोंखाल।	समयः 13:00
4	विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत सिरोली-खिटोटिया मोटर मार्ग के डामरीकरण व सुदृढीकरण कार्य का शिलान्यास। लागत- 544.74 लाख	ग्राम खिटोटिया, विकासखण्ड बीरोंखाल।	समयः 15:10

दिनांक 04 दिसम्बर 2026 (शुक्रवार)

क्र0सं0	कार्य का नाम	स्थान	समय
1	विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत भगवती तलैया-कमलिया-संराईखेत मोटर मार्ग के 05 किमी0 में आर0सी0सी0 मोटरसेतु के निर्माण कार्य का लोकार्पण। लागत- 271.97 लाख	विकास खण्ड मुख्यालय बीरोंखाल।	समयः 10:30
2	विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत फरसाड़ी-गडकोट-छांछरों मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण कार्य का शिलान्यास। लागत- 37.16 लाख।		
3	विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 से हस्तांतरित सिसई-डागु-थापला मोटर मार्ग की मरम्मत कार्य का शिलान्यास। लागत- 179.54 लाख।		

पूर्व की भांति वन्यजीव प्रतिपालक की तैनाती की उठी मांग

जयन्त प्रतिनिधि।कोटद्वार : कोटद्वार क्षेत्र में लगातार बढ़ती मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं और वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर सेवानिवृत्त वन अधिकारियों एवं कर्मचारी कल्याण समिति ने पूर्व की भांति वन्यजीव प्रतिपालक की तैनाती की मांग उठाई है। इस संबंध में समिति ने वन विभाग को पत्र भेजकर पुरानी व्यवस्था बहाल करने का अनुरोध किया है। समिति की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2011-12 के बाद कोटद्वार में वन्यजीव प्रतिपालक की व्यवस्था में बदलाव किया गया। इससे पहले कोटद्वार में वन्यजीव प्रतिपालक की तैनाती रहती थी, जिनके अधीन वन्यजीव रक्षकों की टीम कार्य करती थी। यह टीम वन्यजीवों की सुरक्षा, निगरानी और संरक्षण से जुड़े कार्यों को देखती थी। पत्र में कहा गया है कि पुरानी व्यवस्था समाप्त होने के बाद वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही विभागीय स्तर पर जिम्मेदारियों का उचित निर्वहन करने में भी कठिनाइयां सामने आ रही हैं। समिति ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में कोटद्वार क्षेत्र में मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए प्रभावी निगरानी व्यवस्था बेहद जरूरी है। वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जान-माल की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। समिति ने वन विभाग से मांग की है कि कोटद्वार में पूर्व की भांति वन्यजीव प्रतिपालक की तैनाती की जाए, ताकि वन्यजीव संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया जा सके। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद पंत, हरीश चंद्र भट्ट, केशीराम निराला आदि मौजूद रहे।

लिखित आदेश तक जारी रहेगा आंदोलन

श्रीगनर गढ़वाल : मानदेय वृद्धि सहित अन्य मांगों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना गुरूवार को 15वें दिन भी तहसील परिसर में जारी रहा। धरना स्थल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने नारेबाजी भी की। संगठन की खिर्सू ब्लॉक अध्यक्ष आशा भट्ट ने कहा कि बायोमीट्रिक उपस्थिति से मुक्त रखने, 18 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देने सहित अन्य प्रमुख मांगें पूरा होने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहा कि जब तक सरकार लिखित आदेश जारी नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। गुरूवार को ललिता, आशा भट्ट, गंगोत्री देवी, लक्ष्मी देवी, अंजना, यशोदा, विनीता, प्रिया, सोनाली, मीनाक्षी आदि धरने पर बैठीं।

पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान

श्रीनगर गढ़वाल : मेडिकल कॉलेज के छात्र-छात्राओं को नशे से दूर रखने के लिए पुलिस ने दो छात्रावासों में जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए इससे दूर रहने की अपील की।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुत्र भाष्कर चन्द उर्फ भोलू मेरे कहने सुनने में नहीं आ रहा है। मैं अपने पुत्र भाष्कर चन्द उर्फ भोलू को अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल करता हूं। मेरे पुत्र द्वारा किया गया कोई भी आपराधिक कृत्य की समस्त जिम्मेदारी मेरे पुत्र की रहेगी, इसमें मेरा व मेरे परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

राकेश चन्द पुत्र स्व0 घनानन्द निवासी सिमलचौड़, पट्टी सुखरौ, तहसील कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
(0639/21)

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सेना के अभिलेखों में मेरी पुत्री प्रीति गुसाई की जन्मतिथि भूलवश 13 अप्रैल 2003 दर्ज हो गई है, जो कि गलत है, जबकि मेरी पुत्री प्रीति गुसाई की सही जन्मतिथि 16/10/2003 है, जो उसके समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र में भी दर्ज है। अतः मेरे सेना के अभिलेखों में मेरी पुत्री प्रीति गुसाई की सही जन्मतिथि 16/10/2003 दर्ज की जाये।

आर्मी नंबर 3500766-Hav कलम सिंह गुसाइ पुत्र श्री गजे सिंह निवासी ग्राम नन्दपुर, पोस्ट ऑफिस पदमपुर मोटाढाक, वार्ड नंबर 30, तहसील कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
(0638/21)

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
कॉरपोरेट आईडेन्टीटी संख्या : U40109UP2001SG025867/2358
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नैनीडांडा

निविदा विस्तारीकरण सूचना

इस खण्ड के द्वारा पूर्व में प्रकाशित निविदा संख्या – 13/2026–27 जोकि दिनांक– 26/11/2026 को खोली जानी थी। अपरिहार्य कारणों से उक्त निविदा के प्रपत्र क्रय करने की तिथि को दिनांक– 11/12/2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे तक विस्तारित की जाती है एवं उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख अद्योहस्ताक्षरकर्ता अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपराह्न 15:30 बजे सार्वजनिक रूप से खोली जायेगी। अन्य नियम एवं शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

पत्रांक : 1184/वि0वि0ख0(नै0)/उपाकालि0/टी–6
दिनांक : 26.11.2026

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड– नैनीडांडा

विद्युत बिलों के 24x7 आनलाईन भुगतान हेतु www.upcl.org पर जायें
"राष्ट्र हित में बिजली बचाएं" (Customer Care Toll Free no. 1800 419 0405)

संविधान दिवस के अवसर पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : बी.एड. विभाग में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय संविधान के महत्व, उसके मूल्यों, मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना बीतथा उनमें अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता विकसित करना था। आज का कार्यक्रम महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. डी.एस. नेगी जी की अध्यक्षता में सम्पन्न कराया गया। उन्होंने अपने संबोधन में भारतीय संविधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संविधान हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। यह हमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का संदेश देता है। उन्होंने विद्यार्थियों को संविधान के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने तथा एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। विभागाध्यक्ष डॉ. बी.सी. शाह ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने संविधान दिवस के महत्व को बताते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने संवैधानिक अधिकारों के साथ–साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को संविधान का सम्मान करने और देश के विकास में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के संयोजक एस० के० आर्य सर द्वारा संविधान की रुपरेखा और



उसके निर्माण और उद्देशिका से सभी को परिचित कराते हुए, संविधान को कर्तव्य और अधिकार का एक लिखित दस्तावेज बताया । कार्यक्रम में उपस्थित अन्य शिक्षकगण डॉ. सुशील चंद बहुगुणा, डॉ. एस.के. आर्य, डॉ. डी.के. मौर्य एवं डॉ. डी.बी. सिंह अरविन्द दुदपुड़ी ने भी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया तथा संविधान के मूल्यों और लोकतांत्रिक आदर्शों के महत्व पर अपने विचार साझा किए। इसके पश्चात राजनीति विज्ञान विभाग की प्राध्यापिका डॉ. ऐश्वर्या राणा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने भारतीय संविधान की विशेषताओं, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के महत्व पर प्रकाश डाला एवं संविधान की वर्तमान समय में प्रासंगिकता को स्पष्ट करते हुए, उन्होंने कहा कि संविधान केवल नियमों और कानूनों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह देश की एकता, समानता और न्याय का आधार है। उन्होंने विद्यार्थियों को संविधान के प्रति जागरूक रहने तथा उसके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का मंच संचालन बी.एड. विभाग की छात्रा अदिति रावत द्वारा किया गया। उन्होंने पूरे कार्यक्रम का संचालन सुव्यवस्थित ढंग से किया तथा सभी अतिथियों, शिक्षकगण एवं प्रतिभागियों का उचित रूप से स्वागत एवं परिचय कराया। इस प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल के रूप में अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. निशांत भट्ट एवं राजनीति विज्ञान विभाग की डॉ. ऐश्वर्या राणा उपस्थित रहे। उन्होंने प्रतिभागियों के भाषणों को ध्यानपूर्वक सुना तथा उनके विचारों, विषय की समझ और प्रस्तुतीकरण के आधार पर मूल्यांकन किया। भाषण प्रतियोगिता में बी.एड. विभाग के अनेक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। सभी प्रतिभागियों ने संविधान दिवस से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने भारतीय संविधान की विशेषताओं, मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, लोकतंत्र, समानता एवं न्याय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। सभी प्रतिभागियों ने पूरे आत्मविश्वास और उत्साह के साथ अपनी बात रखी। कार्यक्रम का समापन डा० एस० सी० बहुगुणा जी द्वारा सभी उपस्थित अतिथियों, निर्णायक मंडल एवं शिक्षकगण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए किया गया। यह प्रतियोगिता विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक एवं उत्साहपूर्ण रही। इस आयोजन के माध्यम से विद्यार्थियों को भारतीय संविधान के महत्व को समझने तथा अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ।

न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लोकतंत्र की आत्मा

श्रीनगर गढ़वाल : हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विवि के डॉ. आंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र (डीएसीई) की ओर से संविधान दिवस के अवसर पर चौरास परिसर के एकेडमिक एक्टिविटी सेंटर में 'हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान' विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि कुलपति प्रो. श्री प्रकाश सिंह के नेतृत्व में सभी प्रतिभागियों ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन कर संवैधानिक मूल्यों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। कहा गया कि शिक्षण संस्थाएं विद्यार्थियों में संवैधानिक चेतना विकसित करें। कुलपति प्रो. सिंह ने कहा कि परिवार संस्कारों की पहली पाठशाला है और शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों में संवैधानिक चेतना, अनुशासन व मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता विकसित करनी चाहिए। प्रो. मदन मोहन सेमवाल ने कहा कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लोकतंत्र की आत्मा हैं जिन्हें दैनिक व्यवहार में अपनाना आवश्यक है। विशिष्ट अतिथि सीओ सदर/पौड़ी दिव्येश उपाध्याय ने सोशल मीडिया की सूचनाओं के सत्यापन, अफवाहों से बचाव, परीक्षा के दबाव में धैर्य और नशे से दूर रहने का संदेश दिया। वहीं डीएसडब्ल्यू प्रो. ओपी. गुसाईं ने संविधान निर्माण में डॉ. भीमराव आंबेडकर व संविधान सभा के योगदान पर प्रकाश डाला। निदेशक प्रो. हरि भजन सिंह चौहान ने जिम्मेदार नागरिकता पर बल दिया। (एजेंसी)

छात्र–छात्राओं को दिलाई संविधान की शपथ



जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में संविधान दिवस के अवसर पर राजनीति विज्ञान विभाग में संविधान दिवस का आयोजन किया गया । इस अवसर पर महाविद्यालय के संरक्षक व प्राचार्य प्रो डीएस नेगी द्वारा छात्र–छात्राओं को संविधान की शपथ दिलवाई गयी । इस अवसर पर प्राचार्य ने सम्बोधित करते हुये कहा कि अधिकार हमें शक्ति देते हैं और कर्तव्य हमें जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं ।राजनीति विज्ञानं विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम मे विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिसमे निबंध प्रतियोगिता में सुशांत एमए फर्स्ट सेम ने प्रथम, जिया प्रवीन बीए थर्ड सेम ने द्वितीय, साक्षी एमए फर्स्ट सेम तृतीय स्थान प्राप्त किया । पोस्टर प्रतियोगिता में प्राची नेगी बीए फर्स्ट सेम ने प्रथम ,सुहानी काला एमए फर्स्ट सेम ने द्वितीय, सृष्टि बिष्ट बीए फर्स्ट सेम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया ।भाषण प्रतियोगिता में जगदीश एमए थर्ड सेम ने प्रथम, अपूर्व बीए थर्ड सेम ने द्वितीय, इकरा बीए फर्स्ट सेम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया ।निर्णयक मंडल मे डॉ प्रताप सिंह बिष्ट ,डॉ मीरा कुमारी, डॉ निशांत भट्ट, डॉ नवरत्न सिंह व डॉ वर्षा सिंह रहे । इस अवसर पर राजनीति विज्ञान की विभाग प्रभारी डॉ निरंजना शर्मा द्वारा संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि तथा प्रासंगिकता पर विचार व्यक्त किए गये। डॉ ऐश्वर्या राणा ने संविधान को राष्ट्र की आत्मा और लोकतंत्र की आधारशिला बताया व कहा कि संविधान का सम्मान , उसके आदर्शों और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। कार्यक्रम का संचालन एम ए प्रथम सेम के छात्र सुशांत द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में डॉ बिशन लाल द्वारा आमंत्रित अतिथियों, छात्र–छात्राओं प्रतिभागियों व निर्णायक मंडल का मंच से धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

पशुपालकों को मिलेगी पशु चरी

श्रीनगर गढ़वाल : दुग्ध उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए जिला योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत पशु चरी उपलब्ध कराई जाएगी। आंचल डेयरी की ओर से उन पशुपालकों को योजना का लाभ दिया जाएगा जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पशुओं के लिए चरी-नाद नहीं बना पा रहे हैं। इसके लिए दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आंचल डेयरी श्रीनगर के प्रधान प्रबंधक श्रवण कुमार शर्मा ने बताया कि योजना के तहत ऐसे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी जो नियमित रूप से दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को दूध उपलब्ध करा रहे हैं। समितियों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है। (एजेंसी)

छात्रों को नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए किया प्रेरित



जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : स्वास्थ्य विभाग पौड़ी द्वारा राजकीय पॉलिटेक्निक पाबौ में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मेघना असवाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 4.0 के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित छात्र-छात्राओं को तम्बाकू उपयोग से पड़ने वाले शारीरिक, मानसिक दुष्प्रभावों की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान छात्रों को तम्बाकू मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मेघना असवाल ने कहा कि तम्बाकू मुक्त युवा अभियान का उद्देश्य युवा वर्ग को तम्बाकू, नशे आदि की लत से दूर करने के साथ ही नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में नोडल अधिकारी डॉ. अलीशा सचदेवा ने छात्रों को जानकारी देते हुए बताया कि तम्बाकू उपयोग से कैंसर, हृदय रोग, सांस, मुंह दांतों से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ता है। तम्बाकू केवल उसका सेवन करने वाले व्यक्ति को ही नहीं बल्कि आस पास मौजूद लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि छात्रों को गलत आदतों, नशा, तम्बाकू आदि के प्रयोग को लेकर साथियों के दवाब से बचना चाहिए। उन्होंने छात्रों को अपने आस पास के लोगों को तम्बाकू के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूक करने हेतु प्रेरित किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य शालिग्राम, प्रभारी चिकित्साधिकारी पाबौ डॉ. पंकज सिंह, सपना पंवार, अरुणा उनियाल आदि मौजूद रहे।

संक्षिप्त समाचार

कार्य बहिष्कार के बाद भी ड्यूटी करने पर 47 पीआरडी जवानों पर की कार्रवाई

गोपेश्वर। समान कार्य–समान वेतन और वर्षभर रोजगार की मांग के लिए प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) हित संगठन चमोली के जवानों का कार्य बहिष्कार बृहस्पतिवार को भी जारी रहा। इस दौरान कार्य बहिष्कार के बावजूद ड्यूटी कर रहे 47 जवानों को धरना स्थल पर लाया गया। संगठन ने इन कर्मियों से अर्थदंड भी वसूला और उन्हें संगठन से पृथक करने का निर्णय लिया है।

बृहस्पतिवार को पीआरडी जवानों ने विकास भवन परिसर में धरना दिया। संगठन ने कार्य बहिष्कार के बावजूद 52 सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे कर्मियों को चिह्नित करने के लिए दस सचल टीमें गठित की हैं। जिलाध्यक्ष करण सिंह फरस्वाण और महामंत्री सुनीता सती ने सभी जवानों से एकजुट होकर आंदोलन में शामिल रहने और ड्यूटी पर नहीं जाने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि संगठन के निर्णय के विपरीत ड्यूटी करने वाले जवानों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कार्यबहिष्कार के कारण सरकारी वाहनों के चालक और अधिकारियों के लिए खाना बनाने वाले कर्मी भी ड्यूटी से दूर रहे। संगठन का कहना है कि जवान समान कार्य के बदले सम्मान और अधिकारों की मांग कर रहे हैं। जब तक मांगों पर शासनादेश जारी नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर बलवंत सिंह राणा, नरेंद्र सिंह, महेंद्र लाल, हर्ष लाल, गजपाल लाल, जयपाल, महेंद्र राणा, पुष्पा, अनीता, कुलदीप सिंह गड़िया, जितेंद्र सिंह, सतेंद्र सिंह और मोहन सिंह रावत आदि मौजूद रहे।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना जारी



गोपेश्वर। विभिन्न मांगों के लिए आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बृहस्पतिवार को भी कलेक्ट्रेट परिसर में धरना जारी रहा। चमोली जिले के ज्योतिर्मठ, दशोली और नंदानगर ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नौ दिनों से कार्यबहिष्कार कर आंदोलन कर रही हैं। आंदोलनकारियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 140 रुपये प्रतिदिन करने, केंद्र सरकार की ओर से 150 रुपये प्रतिदिन करने, सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये की धनराशि देने की मांग भी उठाई गई। कार्यकर्ताओं ने मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। धरने पर सरिता, उमा, अनिता नेगी, सरोजनी, विनीता, रेखा, दीपा देवी, मंजू रावत, उर्मिला नेगी, प्रभा और कविता आदि मौजूद रहे।

संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई

गोपेश्वर। चमोली जिले में बुधवार को संविधान दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों में कार्यक्रम आयोजित कर संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई।

जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यशाला में जिला जज बिंध्याचल सिंह ने कहा कि संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य नागरिकों को संवैधानिक अधिकारों, कर्तव्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्र–छात्राओं को शपथ दिलाई। जीआईसी गोपेश्वर के विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकाली। जिला कार्यालय में परियोजना निदेशक आनंद सिंह भाकुनी ने शपथ दिलाई। पुलिस लाइन में सीओ मदन सिंह बिष्ट ने कार्यक्रम कराया। पीजी कॉलेज पोखरी, ज्योतिर्मठ सहित विभिन्न कार्यालयों और कांग्रेस कार्यालय में भी संविधान दिवस मनाया गया। सभी ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा का संकल्प लिया।

नशे में धुत चालक 25 यात्रियों की जिंदगी से कर रहा था खिलवाड़

दुगड्डा बैरियर पर पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया बस चालक, बस सीज कर किया गिरफ्तार

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : नशे में वाहन चलाने की लापरवाही पहाड़ी सड़कों पर कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। इसके बावजूद कुछ चालक अपनी जिम्मेदारी को लेकर गंभीर नजर नहीं आते। पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से लगातार चेकिंग अभियान चलाए जाने के बाद भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। गुरुवार को दुगड्डा बैरियर पर एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां शराब के नशे में धुत चालक 25 यात्रियों को लेकर पहाड़ी मार्ग पर बस दौड़ा रहा था। समय रहते पुलिस की चेकिंग में चालक की लापरवाही पकड़ में आ गई, जिससे संभावित



हादसा टल गया।गुरुवार सुबह दुगड्डा बैरियर के समीप पुलिस की टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान कोटद्वार की ओर से आ रही एक यात्री बस को रोककर चालक की जांच की गई। बातचीत के दौरान चालक की आवाज लड़खड़ाने पर पुलिस को शक हुआ। इसके बाद एल्कोमीटर से जांच की गई तो चालक के शराब के सेवन की पुष्टि हुई। पूछताछ में चालक की पहचान मुकेश कुमार, निवासी कोटद्वार के रूप में हुई। जांच में पता चला कि बस कोटद्वार से 25 यात्रियों को लेकर सतपुली की ओर जा रही थी। शराब के नशे में बस चला रहा चालक न केवल यातायात नियमों की अनदेखी कर रहा था, बल्कि यात्रियों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहा था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चालक को गिरफ्तार कर बस सीज कर दी। वहीं, बस में सवार सभी 25 यात्रियों को दूसरे वाहनों से सुरक्षित उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया।

वाणिज्य संकाय परिषद का गठन, अंजली बनी अध्यक्ष

जयन्त प्रतिनिधि। लैंसडौन : भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जयहरीखाल के वाणिज्य संकाय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 'वाणिज्य संकाय परिषद का गठन किया गया। जिसमें अंजली को अध्यक्ष चुना गया। छात्र परिषद में अंजली (एम.कॉम. द्वितीय वर्ष) को अध्यक्ष, प्रिया (बी.कॉम. तृतीय वर्ष) को उपाध्यक्ष, साक्षी (एम.कॉम. प्रथम वर्ष) को सचिव, तनु अग्रवाल (बी.कॉम. द्वितीय वर्ष) को कोषाध्यक्ष तथा सक्षम नेगी (बी.कॉम. प्रथम वर्ष) को सह-सचिव चुना गया। इस अवसर पर वाणिज्य विभागाध्यक्ष डॉ. विनय देवलाल ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए परिषद की विशेषताओं एवं इसके महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विभागीय परिषद विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क, संगठनात्मक कौशल और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का एक सशक्त मंच है। साथ ही यह परिषद विद्यार्थियों एवं प्राध्यापकों के बीच संवाद का सेतु बनकर विभाग की शैक्षणिक व रचनात्मक गतिविधियों को नई दिशा देती है। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. डॉ. एल. आर. राजवंशी सहित संकाय के प्राध्यापक डॉ. फकीर सिंह एवं डॉ. एस.ए. अंसारी ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए छात्र हित में कार्य करने की अपील की।

एसआईआर में कट गया नाम तो न घबराएं

उत्तरकाशी। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के बीच पुराने मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने स्थिति साफ कर दी है। ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं मिलने पर दोबारा आवेदन करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए फॉर्म–6 और उसके घोषणा पत्र को लेकर जारी असमंजस भी दूर कर दिया है।

चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से कट गए हैं या शामिल नहीं हो पाए हैं, वे बिना किसी डर के नया वोट बनवाने के लिए फॉर्म–6 और उसका घोषणा पत्र भर सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने इस संबंध में स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी किए हैं।आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर हुए पुराने मतदाताओं को नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म–6 भरने में घबराने की जरूरत नहीं है। उन पर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आयोग ने अपने इस रुख के समर्थन में दिल्ली हाईकोर्ट के 14 अक्तूबर के फैसले का हवाला भी दिया है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि पूर्व में मतदाता रहने के बावजूद ड्राफ्ट सूची से नाम कटने पर फॉर्म–6 भरने को गलत घोषणा नहीं माना जा सकता और ऐसे आवेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही होनी चाहिए।

भ्रम को तथ्यों व कानून से दूर करने की अपील

श्रीनगर गढ़वाल : संविधान दिवस के अवसर पर भाजपा विधि प्रकोष्ठ, पौड़ी गढ़वाल द्वारा बार भवन, श्रीनगर में संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण में राष्ट्रवादी अधिवक्ताओं की भूमिका विषय पर जिला स्तरीय अधिवक्ता गोष्ठी आयोजित की गई।

अधिवक्ताओं ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुलभ न्याय पहुंचाने, संवैधानिक नैतिकता बनाए रखने, मौलिक कर्तव्यों के पालन और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर फैलने वाले भ्रम को तथ्यों व कानून से दूर करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संयोजन जिला संयोजक अनूप श्रीपांथरी ने किया और संचालन सह-संयोजक विकास पंत ने किया। इस अवसर पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष परमेश चंद्र जोशी, वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र पाल सिंह रावत, बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन सिंह भंडारी, प्रदीप मैठाणी, नितेश भारती आदि मौजूद रहे। (एजेंसी)

किसानों के हित में योजना बना रही सरकार

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उन्हें खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। काश्तकारों को खेती के लिए सरलता से ऋण उपलब्ध कराने के साथ ही कृषि और स्वरोजगार के नए अवसर मुहैया कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे किसान अपनी आर्थिकी को बेहतर बना सकेंगे। यह बात विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कही।

गुरुवार को देवी रोड स्थित एक बारातघर में सुखरो देवी मंदिर बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति की वार्षिक सामान्य निकाय बैठक आयोजित की गई। इस दौरान आयोजित शिविर में किसानों को सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं और ऋण सुविधाओं की जानकारी दी गई। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सशक्त बनेगी। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियां किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सरकार का प्रयास है कि किसानों को समय पर और सरल प्रक्रिया के माध्यम से ऋण उपलब्ध हो, जिससे वे बेहतर तरीके से खेती कर अपनी आय बढ़ा सकें।

उन्होंने किसानों से सरकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने शिविर में लगाए गए विभिन्न स्टालों का निरीक्षण कर उत्पादों की जानकारी भी ली। कार्यक्रम में समिति के चेयरमैन पंकज रावत, जीएम संजय रावत, डीसीडीएफ रवींद्र नेगी, मंडल अध्यक्ष प्रेमा खंतवाल, अतिया त्रिपाठी, जितेंद्र नेगी, रजत भट्ट, सहकारी समिति की अध्यक्ष अमिता बिष्ट, उमेश त्रिपाठी, वरिष्ठ नागरिक पातीराम ध्यानी, विजय लखेड़ा, जीवन कोठारी और समिति की सचिव पुष्पा देवी सहित सहकारिता विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे।

संविधान के मूल्यों और महिला अधिकारों के प्रति जागरूक रहें युवा

निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र-छात्राएं सम्मानित

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : संविधान दिवस एवं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर गुरुवार को हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के बीजीआर परिसर पौड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरुकता शिविर आयोजित किया गया।

शिविर में विद्यार्थियों को संविधान के मूल्यों, मौलिक अधिकारों, कानूनी सहायता तथा महिलाओं के कानूनी एवं संवैधानिक अधिकारों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान आयोजित निबंध प्रतियोगिता में खुशबू भट्ट ने प्रथम, शिवम नेगी ने द्वितीय, निशांत गोदियाल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं चित्रकला प्रतियोगिता में सुरभि थपलियाल प्रथम रहीं। विजेता छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया



गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सिविल जज नाजिश कलीम ने कहा कि संविधान देश के लोकतंत्र की आधारशिला है, जो प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने विद्यार्थियों से संविधान के आदर्शों और मौलिक कर्तव्यों को अपने जीवन में आत्मसात करने तथा एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान किया। उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए विधिक सेवा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, घरेलू हिंसा और लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इनके उन्मूलन के लिए समाज में जागरूकता और समानता की भावना विकसित करना आवश्यक है। उन्होंने छात्र-छात्राओं को महिलाओं के कानूनी एवं संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देते हुए इन अधिकारों के प्रति स्वयं जागरूक रहने और समाज के अन्य लोगों को भी जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर रिटेनर अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह रावत, विधि विभागाध्यक्ष रामप्रकाश, सहायक प्राध्यापक पंकज कार्की, सोना धंगार सहित विधि विभाग के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

अमेरिका: न्यू ऑरलियन्स से फ्लोरिडा जा रहा विमान समंदर में गिरा, दो बच्चों समेत छह लापता; बचाव अभियान जारी

मिसिसिपी, एजेंसी। मिसिसिपी के तट के पास मंगलवार को एक छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद, बचाव दल छह लोगों की तलाश कर रहे हैं, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। 'सेसना 210' नाम का यह विमान मैक्सिको की खाड़ी में, मिसिसिपी के पास्कागौला और हॉर्न आइलैंड के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हॉर्न आइलैंड 'गल्फ आइलैंड्स नेशनल सीशोर' का हिस्सा है। कोस्ट गार्ड के प्रवक्ता जुआन रॉस ने बताया कि बचाव दल को पानी में तैरती हुई तीन लाइफ जैकेट, एक लाइफ राफ्ट और विमान का केबिन मिला है, लेकिन विमान में सवार चार वयस्क और 8 व 10 साल के दो बच्चे अभी तक नहीं मिले हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट 'फ्लाइटअवेयर' के अनुसार, यह सेसना विमान न्यू ऑरलियन्स से फ्लोरिडा के फोर्ट मायर्स जा रहा था। इस दुर्घटना की जांच करने वाले 'फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन' और 'नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड' ने मंगलवार को बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी है। इस महीने की शुरुआत में, दक्षिण फ्लोरिडा में एक 'लियरजेट 60' बिजनेस जेट सीधे जमीन से टकरा गया था, जिसमें सवार सभी नौ लोगों की मौत हो गई थी। इस भयानक हादसे को कारों में बैठे लोगों ने अपने वीडियो में कैद कर लिया था।

अमेरिका में एच5एन1 से एक व्यक्ति की मौत- डब्ल्यूएचओ

वाशिंगटन, एजेंसी। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अमेरिका के वाशिंगटन में एच5एन1 वायरस से इंसानों के संक्रमित होने की पुष्टि की है। इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हालांकि संगठन के मुताबिक आम जनता को इससे कोई खास खतरा नहीं है। ये मामले 16 अक्तूबर से 4 नवंबर के बीच सामने आए। इनमें से एक मौत का मामला भी है, जो संक्रमित डेयरी पशुओं या उनसे दूषित वातावरण के संपर्क में आने के बाद हुई पहली दर्ज मौत है। ये तीनों मामले वयस्कों के हैं, जो वॉशिंगटन राज्य की याकिमा काउंटी में डेयरी पशु फार्मों पर काम करते थे। इन फार्मों के डेयरी पशुओं में हाल ही में यह वायरस पाया गया था। वायरस के संपर्क में आए लोगों और उनके करीबी संपर्कों की जांच और निगरानी की जा रही है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि बर्ड फ्लू वायरस मुख्य रूप से जानवरों में फैलते हैं और इंसानों को बहुत कम संक्रमित करते हैं। हालांकि, संक्रमित जानवरों या दूषित वातावरण के संपर्क में आने पर इंसानों में भी कभी-कभार संक्रमण हो सकता है।

सोलोमन द्वीप ने ऑस्ट्रेलिया को बनाया अपना प्रमुख सुरक्षा साझेदार, चीन के लिए सैन्य अड्डे का रास्ता बंद

बीजिंग, एजेंसी। दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच सोलोमन द्वीप ने ऑस्ट्रेलिया को अपना प्रमुख सुरक्षा साझेदार घोषित किया है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने बुधवार को एक नए द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में स्पष्ट किया गया है कि सोलोमन द्वीप में किसी भी विदेशी देश का सैन्य या सुरक्षा अड्डा नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री मैथ्यू वेले ने संयुक्त बयान में समझौते की जानकारी दी। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है, जब खबरें हैं कि सोलोमन द्वीप 2022 में चीन के साथ हुए पांच वर्षीय सुरक्षा समझौते को आगे नहीं बढ़ाएगा। हालांकि, वेले ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि चीन के साथ समझौते में गोपनीयता की शर्त है और दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है।

हांगकांग अग्निकांड के एक साल बाद भी पीड़ितों को नहीं मिला इंसाफ

हांगकांग , एजेंसी। हांगकांग में पिछले साल हुए भीषण अग्निकांड के एक साल बाद भी पीड़ित परिवार सदमे और न्याय की उम्मीद के बीच जिंदगी गुजार रहे हैं। 26 नवंबर 2025 को वांग फुक कोर्ट आवासीय परिसर की सात इमारतों में लगी आग में 168 लोगों की मौत हो गई थी। यह शहर में कई दशकों की सबसे भीषण आग की घटनाओं में से एक थी। जांच में सामने आया कि आग संभवतः जलती हुई सिगरेट से लगी और तेजी से फैलने वाले मचान के ज्वलनशील पदार्थों ने इसे भयानक रूप दे दिया। हादसे से पहले भी निवासियों ने निर्माण कार्य के दौरान आग से जुड़े खतरों की शिकायत की थी।

कोलंबिया के सुपरमार्केट में 20 लोग बंधक हथियारबंद लोगों ने 18 करोड़ की फिरौती मांगी

कार्टाजेना, एजेंसी। कोलंबिया के कार्टाजेना शहर में मंगलवार को कुछ हमलावरों ने 20 लोगों को बंधक बना लिया। रॉयटर्स के मुताबिक, उन्होंने सुबह करीब 8 बजे सुपरमार्केट में घुसकर कैश लेकर जा रही बख्तरबंद गाड़ी को लूटने की कोशिश की थी। इस दौरान सुरक्षा कैमरों पर नजर रख रहे कर्मचारियों ने पैनिक बटन दबाकर पुलिस को सूचना दे दी। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए। पुलिस को देखकर हमलावर सुपरमार्केट में घुस गए। यहां उन्होंने लोगों को बंधक बना लिया।



20 लाख डॉलर और दो सुरक्षा गाड़ियां मांगीं : रिपोर्ट्स के मुताबिक, बदमाशों ने 20 लाख डॉलर (करीब 18 करोड़ रुपए), दो बख्तरबंद गाड़ियां और सुरक्षित रास्ता देने की मांग की। वे कार्टाजेना से करीब 130 किलोमीटर दूर बैरेंक्विला शहर जाना चाहते थे। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों में हथियारबंद और चेहरे ढके बदमाश सुपरमार्केट में घुसते दिखाई दिए। कुछ तस्वीरों में बंधक बने लोग कुर्सियों पर बैठे दिखे। उनके हाथ बंधे हुए थे और बदमाश हथियार लेकर उनके पीछे पहरा दे रहे थे।

5 बुजुर्ग महिलाओं को छोड़ दिया : राष्ट्रपति अबेलार्डो डी ला एस्प्रिएला ने पहले बताया था कि बदमाशों ने 30 लोगों को बंधक बनाया है। इनमें से 5 बुजुर्ग महिलाओं समेत 10 को छोड़ दिया गया। बाकी लोगों को छुड़ाने के लिए पुलिस और सेना के जवानों के साथ खास सुरक्षा टीमें भी तैनात किए गए। रॉयटर्स के मुताबिक, पुलिस ने सुपरमार्केट और आसपास के इलाके को घेर लिया है। पास की इमारतों की छतों पर भी हथियारबंद जवान तैनात किए गए। इस बीच, इन्हें पकड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान के चलते शहर के राफेल नुनेज एयरपोर्ट पर 45 मिनट तक विमानों की लैंडिंग रोक दी गई। सुपरमार्केट चलाने वाली कंपनी ग्रुपो एक्सिटो ने बयान जारी कर कहा कि लोगों की जान और उनकी सुरक्षा उसकी पहली प्राथमिकता है। कंपनी ने बताया कि मामले को संबंधित सरकारी एजेंसियां संभाल रही हैं।

राष्ट्रपति ने क्या बताया : सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने स्थानीय मीडिया के हवाले से ये जानकारी दी। राष्ट्रपति अबेलार्डो डी ला एस्प्रिएला ने बताया कि नकाबपोश हथियारबंद लोगों ने पहले नकदी ले जा रहे एक बख्तरबंद वाहन को लूटने की कोशिश की थी। हालांकि, सुरक्षा कैमरों की निगरानी कर रहे कर्मचारियों ने पुलिस को अलर्ट कर दिया, जिसके बाद बदमाश पास के एक सुपरमार्केट में घुस गए और वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया। राष्ट्रपति ने एक्स पोस्ट के जरिए बताया कि, बदमाशों ने शुरुआत में करीब 30 लोगों को बंधक बनाया था। इनमें से पांच बुजुर्ग महिलाओं को बाद में रिहा कर दिया गया। शेष लोगों को मुक्त कराने के लिए पुलिस और सैन्य बलों की विशेष इकाइयों को तैनात किया गया।

कहां हुई यह घटना : यह घटना कार्टाजेना के ला कास्टेलाना इलाके में स्थित एक्सितो सुपरमार्केट में हुई। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में लोगों को सुपरमार्केट से बाहर भागते देखा गया। स्थानीय मीडिया ने आसपास की इमारतों पर तैनात स्नाइपरों की तस्वीरें भी प्रसारित कीं। कुछ फुटेज में सुपरमार्केट के भीतर लोग हाथ बंधे होने की स्थिति में खिड़कियों के पास घुटनों के बल बैठे दिखाई दिए। हालांकि, इन तस्वीरों और वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। कार्टाजेना के ला कास्टेलाना इलाके स्थित एक्सितो सुपरमार्केट में मंगलवार (स्थानीय समयानुसार) को यह घटना हुई। राष्ट्रपति एबेलार्डो दे ला एस्प्रिएला के अनुसार, हथियारबंद लोगों ने पहले एक मॉल से नकदी ले जा रहे बख्तरबंद वाहन को लूटने की कोशिश की। सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय होने और पुलिस के पहुंचने पर वे पास के सुपरमार्केट में घुस गए और वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया। घटना के मद्देनजर कार्टाजेना के राफेल नुनेज हवाईअड्डे पर विमानों की लैंडिंग कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी। बाद में उड़ान संचालन धीरे-धीरे बहाल किया गया।

बंधक बनाने वाले कौन हैं : राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया, 'सुपरमार्केट में लोगों को बंधक बनाने वाले सामान्य अपराधी हैं और उनका किसी गुरिल्ला या अर्धसैनिक संगठन से जुड़ाव सामने नहीं आया है।' यह घटना ऐसे समय हुई है जब देश पहले से ही विद्रोही संगठनों के हमलों और संगठित अपराध की चुनौती से जूझ रहा है। वहीं, मध्य कोलंबिया के विलाविसेंसियो शहर में मेटा प्रांत के गवर्नर कार्यालय को निशाना बनाकर विस्फोटकों से भरी कार में धमाका किया गया। अधिकारियों के मुताबिक, इस हमले में 22 लोग घायल हुए और 80 से अधिक इमारतों को नुकसान पहुंचा। कार में लगभग 100 किलोग्राम विस्फोटक होने की बात सामने आई है।

आतंकवादी नई तकनीक का कर रहे इस्तेमाल, भारत ने दुनिया को किया हैकिंग के खतरे से आगाह

न्यूयॉर्क, एजेंसी। भारत ने दुनिया को आंतकियों के बदलते पैटर्न से आगाह किया है। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत ने तकनीक के दुरुपयोग का हवाला देते हुए हैकिंग के प्रति सतर्क रहने का आह्वान किया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने मंगलवार (स्थानीय समयानुसार) को कहा कि आतंकवादियों और नॉन-स्टेट एक्टर्स द्वारा उभरती तकनीकों का संभावित दुरुपयोग बेहद गंभीर चिंता का विषय है। 'तेजी से होते तकनीकी बदलावों के दौर में संघर्ष समाधान' विषय पर सुरक्षा परिषद की एक चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, 'एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के जरिए अधूरा, गलत या जानबूझकर बदला गया डेटा निर्णय लेने की प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। पी हरीश बोले, 'भारत ने डिजिटल बुनियादी ढांचे, साइबर सुरक्षा और उभरती हुई तकनीकों के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। इससे पता चलता है कि भारत महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और जरूरी नागरिक सेवाओं के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दे रहा है। उन्होंने आगे कहा, 'देश के भीतर, 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम' (आईटी एक्ट) और उससे जुड़े नियम अनधिकृत पहुंच, डेटा के साथ छेड़छाड़ और कंप्यूटर सिस्टम में बाधा डालने के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये नियम सशस्त्र संघर्ष के दौरान भी प्रासंगिक बने रहते हैं। उन्होंने कहा, 'तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति, संघर्ष के स्वरूप और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य को पूरी तरह से बदल रही है। माइक्रोसॉफ्ट के एक अधिकारी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण डिजिटल बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरों की ओर ध्यान दिलाया। कंपनी के कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष फ्रेडरिक हम्फ्रीज ने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट की '2026 डिजिटल डिफेंस रिपोर्ट' के अनुसार, साइबर हमलों का जवाब देने के लिए मिलने वाला समय कम होता जा रहा है। अब सॉफ्टवेयर या सिस्टम में पाई गई नई कमियों का फायदा उठाकर 24 घंटे से भी कम समय में एक सक्रिय हमला किया जा सकता है। इस वजह से, संघर्ष को बढ़ने से रोकना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घटनाओं की पुष्टि करने या इरादों के बारे में बातचीत करने के लिए बहुत कम समय मिलता है। हरीश ने कहा, 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वायत्त (ऑटोनॉमस) सिस्टम और उभरती हुई डिजिटल तकनीकें अभूतपूर्व अवसर तो लाती हैं, लेकिन साथ ही ये पूरे संघर्ष चक्र में नई कमजोरियां और जोखिम भी पैदा करती हैं। '

उन्होंने जोर देकर कहा कि सिस्टम पर इंसानों का नियंत्रण सर्वोपरि होना चाहिए।

इस्राइल का दावा: ईरान बना रहा रासायनिक हथियार; अमेरिका को तेहरान की चेतावनी

यरुशलम, एजेंसी। इस्राइली कार्यवाहक रक्षा मंत्री इस्राइल काट्ज ने ईरान को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान रासायनिक हथियार बना रहा है। इस्राइली मीडिया ने यह जानकारी दी। पत्रकारों से बातचीत में काट्ज ने कहा कि ईरान रासायनिक हथियार विकसित करने की प्रक्रिया में है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि यह कार्यक्रम कितना आगे बढ़ चुका है। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि इन हथियारों को कहां बनाया जा रहा है।

काट्ज ने कहा कि जून 2025 में इस्राइल और अमेरिका ने ईरान के अहम ठिकानों पर हमले किए थे। इसके बाद ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम दोबारा शुरू नहीं किया है। लेकिन, ऐसे संकेत हैं कि वह इसे फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा है।

काट्ज ने कहा, 'अगर हमें पता चलता है कि ईरान इस्राइल पर हमला करने का इरादा रखता है, तो क्या हम सेना को पहले हमला करने और खतरे को नाकाम करने का आदेश नहीं दे सकते? अगर ईरान पहले हम पर हमला करता है, तो यह हमारी नाकामी होगी'। इस्राइल के सरकारी प्रसारक कान ने भी एक रिपोर्ट दी है। इसके मुताबिक, इस्राइल ने इसी महीने की शुरुआत में अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ खुफिया जानकारी साझा की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि ईरान उनके खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस्राइल को एक दशक से भी ज्यादा समय से ईरान के रासायनिक हथियार विकसित करने की जानकारी है। इस्राइली अधिकारियों के इन दावों के बीच ईरान की ओर से भी चेतावनी आई है। ईरान की सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दोल्लाही ने मंगलवार को यह चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने सैन्य ठिकानों को क्षेत्र में कहीं भी ले जाए। वे ईरानी सशस्त्र बलों की मिसाइलों की जद में रहेंगे। मंगलवार को बसीज सप्ताह के मौके पर एक बैठक हुई।

अमेरिका ने अलीबाबा की सात कंपनियों पर लगाया निर्यात प्रतिबंध

वाशिंगटन , एजेंसी। अमेरिका ने उन्नत कंप्यूटिंग उपकरणों और अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर चिप की अनधिकृत इस्तेमालकर्ताओं तक पहुंचने की आशंका के चलते सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड और अलीबाबा की एक सहायक कंपनी समेत सात कंपनियों पर निर्यात प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के उद्योग एवं सुरक्षा ब्यूरो (बीआईएस) ने इन कंपनियों को अपनी 'एंटिटी लिस्ट' में शामिल किया है। इसके बाद अमेरिकी निर्यात नियमों के दायरे में आने वाले उत्पादों, तकनीक और उपकरणों के निर्यात, पुनर्निर्यात या हस्तांतरण के लिए विशेष लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे लाइसेंस के आवेदनों को सामान्यतः खारिज किया जाएगा। ये प्रतिबंध 23 नवंबर से प्रभावी हो गए हैं। हालांकि, इन्हें औपचारिक रूप से 25 नवंबर को अमेरिकी फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित किया गया।



प्रतिबंधों के दायरे में सिंगापुर की मेगास्पीड इंटरनेशनल, स्विफ्टडाटा और एपेक्स एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, मलेशिया की एमएसफ्यूजन, पीटी मेगास्पीड इंटरनेशनल और स्पीडमैट्रिक्स तथा थाईलैंड में मेगास्पीड का परिचालन शामिल है। अमेरिकी कार्रवाई के बाद अलीबाबा ने अपनी सहायक कंपनी एपेक्स को सूची में शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि एपेक्स ने अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आने वाली उन्नत चिप को किसी अनधिकृत पक्ष तक नहीं पहुंचाया है। अलीबाबा ने अपने अधिकारों और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कानूनी रास्ता अपनाने की बात भी कही है। इस बीच, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने मंगलवार को कहा कि मेगास्पीड के खिलाफ उनके देश की जांच अभी जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिंगापुर अमेरिका के निर्यात नियंत्रण कानूनों को लागू नहीं करता, लेकिन वह अपने देश का इस्तेमाल अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए किए जाने के पक्ष में भी नहीं है। वोंग ने कहा, ' सिंगापुर अमेरिकी अधिकारियों की जांच में सहयोग करता है और अपने घरेलू कानूनों के संभावित उल्लंघनों की पड़ताल करता है।' उन्होंने यह भी बताया कि सिंगापुर ने अमेरिका से इस मामले में अतिरिक्त जानकारी मांगी है, लेकिन अभी तक पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। उनके मुताबिक, मेगास्पीड ने एनवीडिया से जो चिप खरीदी थीं, वे सिंगापुर में इस्तेमाल होने के बजाय दूसरे देशों में भेजी गईं। इससे जांच जटिल हो गई है। सिंगापुर अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत कर यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इन चिप का अंतिम इस्तेमाल किन देशों और संस्थाओं ने किया तथा संबंधित दस्तावेजों की सत्यता क्या है। इस मामले की अमेरिकी जांच 2024 में शुरू हुई थी। अमेरिकी वाणिज्य और न्याय विभागों ने 17 नवंबर को जारी संयुक्त बयान में कहा था कि जांचकर्ताओं को संवेदनशील सेमीकंडक्टर चिप की संभावित अनधिकृत आपूर्ति से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों का पता चला है। बयान के अनुसार, वाणिज्य विभाग ने मई 2025 में एनवीडिया से मेगास्पीड को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से की गई बिक्री का रिकॉर्ड मांगा था।

अमेरिका में खसरे का कहर: दो की मौत, इस साल 5838 मामले आए सामने

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में खसरे का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। दो राज्यों विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया में खसरे से जुड़ी दो और मौतें दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही दोनों राज्यों में इस साल इस बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या क्रमशः तीन और नौ हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों से टीकाकरण कराने की अपील की है। विस्कॉन्सिन के स्वास्थ्य सेवा विभाग ने मंगलवार को बताया कि लाफायेट काउंटी में एक वयस्क की खसरे से जुड़ी दिक्कतों के चलते मौत हुई है। परिवार की निजता का सम्मान करते हुए मृतक के बारे में अतिरिक्त जानकारी साझा नहीं की गई। राज्य में इस साल अब तक खसरे के 920 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें शुक्रवार के बाद से सामने आए 88 नए मामले भी शामिल हैं। 918 मामले



अगस्त में शुरू हुए प्रकोप से जुड़े हैं। राज्य में इस साल 20 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है।

पेंसिल्वेनिया में कैसे बढ़ा संक्रमण : वहीं, पेंसिल्वेनिया के स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को सेंटर काउंटी के एक ऐसे निवासी की मौत की पुष्टि की, जो खसरे से संक्रमित पाया गया था और जिसका टीकाकरण नहीं हुआ था। विभाग ने मृतक की उम्र या पहचान से जुड़ी अन्य जानकारी नहीं दी। पेंसिल्वेनिया में इस साल अब तक 46 काउंटियों में खसरे के 1,638 मामले दर्ज किए गए हैं। 18 नवंबर के बाद से 49 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में संक्रमण के कारण 330 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। इस साल खसरे से हुई नौ मौतें छह अलग-अलग काउंटियों में दर्ज की गई हैं। सेंटर काउंटी में यह पहली मौत है।

संक्रमण रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए : पेंसिल्वेनिया में अप्रैल के अंत में संक्रमण फैलना शुरू होने के बाद से स्वास्थ्यकर्मियों ने 287 अस्थायी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से खसरा, मम्प्स और रूबेला (एमएमआर) के 7,400 से अधिक टीके लगाए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि संक्रमण पर काबू पाने के लिए और टीकाकरण केंद्र खोले जाएंगे। देशभर में कितने मामले सामने आए? अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के अनुसार, 19 नवंबर तक देश में खसरे के 5,838 पुष्ट मामले दर्ज किए जा चुके थे। यह संख्या 2025 में पूरे साल दर्ज किए गए 2,289 मामलों से कहीं अधिक है। इस साल सामने आए कुल मामलों में करीब 96 प्रतिशत संक्रमण के प्रकोप से जुड़े हैं। हालांकि, सीडीसी के राष्ट्रीय आंकड़ों की गणना की अंतिम तारीख राज्यों की हालिया रिपोर्ट से पहले की है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि संबंधित राज्यों के स्वास्थ्य विभाग अपने यहां संक्रमण की सबसे ताजा स्थिति की जानकारी देते हैं। विस्कॉन्सिन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि बुखार और शरीर पर चकत्ते जैसे लक्षण दिखाई देने पर सीधे अस्पताल या क्लीनिक जाने के बजाय पहले अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को फोन करें, ताकि दूसरे लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी सावधानियां बरती जा सकें।

प्रवासी परिवारों के आवास संबंधी नियम पर भड़के राज्य, ट्रंप सरकार पर केस

वाशिंगटन , एजेंसी। अमेरिकी राज्यों के एक गठबंधन ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ आवास संबंधी एक नियम को लेकर मुकदमा दायर किया है। इस नियम के तहत उन परिवारों को मिलने वाली किराये की सहायता बंद हो सकती है, जिनके सदस्यों में अमेरिकी नागरिकों के साथ-साथ ऐसे आप्रवासी भी शामिल हैं जो संघीय सहायता पाने के योग्य नहीं हैं। सोमवार को मैसाचुसेट्स की एक संघीय अदालत में दायर मुकदमे में, 'आवास और शहरी विकास विभाग' (एचयूडी) की एक नीति को चुनौती दी गई है। यह नीति सार्वजनिक आवास, रेंटल वाउचर और अन्य सब्सिडी वाले आवास कार्यक्रमों को प्रभावित करती है। कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और मैसाचुसेट्स इस चुनौती का नेतृत्व कर रहे हैं। इनके साथ अन्य राज्य, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो भी शामिल हैं। वे अदालत से इस नियम को रद्द करने और इसे लागू होने से रोकने की मांग कर रहे हैं।



यह विवाद 'मिश्रित-स्थिति' वाले परिवारों से जुड़ा है – ऐसे परिवार जिनमें कुछ सदस्य संघीय आवास सहायता के लिए पात्र हैं, जबकि अन्य सदस्य अपने आव्रजन (इमिग्रेशन) दर्जे के कारण पात्र नहीं हैं। मौजूदा व्यवस्था के तहत, सरकार परिवार की सब्सिडी को केवल पात्र सदस्यों के हिस्से तक सीमित कर देती है। एक अपात्र रिश्तेदार परिवार के साथ रह तो सकता है, लेकिन उसे सब्सिडी का कोई हिस्सा नहीं मिलता। नया नियम इस व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इससे पात्र नागरिक और आप्रवासी लोग सहायता से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि वे किसी ऐसे रिश्तेदार के साथ रहते हैं जो इस सहायता के लिए पात्र नहीं है। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने कहा, 'परिवारों को एक साथ रहने और सिर पर छत होने के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उनके कार्यालय का अनुमान है कि कैलिफोर्निया में 7,000 से अधिक ऐसे 'मिश्रित-स्थिति' वाले परिवार प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें अमेरिकी नागरिक बच्चे भी शामिल हैं। एचयूडी ने 12 नवंबर को अंतिम नियम जारी किया, जो 14 दिसंबर से लागू होगा। इसके तहत, इन आवास कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले या लाभ पाने वाले सभी लोगों को अपनी नागरिकता या पात्र आव्रजन दर्जे का सत्यापन (वेरिफिकेशन) कराना होगा, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो।

विभाग का कहना है कि ये बदलाव संघीय पात्रता शर्तों को लागू करते हैं और सीमित आवास संसाधनों को उन परिवारों तक पहुंचाते हैं, जिनके सभी सदस्य पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं। एचयूडी का अनुमान है कि इस नीति के जरिए सालाना 167 मिलियन से 218 मिलियन डॉलर की रेंटल सहायता उन परिवारों को मिल सकती है जो पूरी तरह से पात्र हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं।

अमेरिकी सैनिक चीन को सेना के सीक्रेट बेच रहा था:मिसाइल और रॉकेट सिस्टम तक की जानकारी दी

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिकी सैनिक पैसों के लिए अपने ही देश की सैन्य जानकारी चीन से जुड़े लोगों को बेच रहा था। वह सेना के सीक्रेट दस्तावेजों की तस्वीरें अपने मोबाइल से खींचता और उन्हें आगे पहुंचाता था। इन दस्तावेजों में मिसाइलों और रॉकेट सिस्टम से जुड़ी अहम जानकारियां थीं। सेना के सीसीटीवी कैमरों में उसकी यह हरकत रिकॉर्ड हो गई। अब उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी का नाम जियान झाओ है। उसकी उम्र 37 साल है। वह वॉशिंगटन के जॉइंट बेस लुईस-मैककॉर्ड में तैनात था। सेना में रहते हुए उसे कई दस्तावेजों और सैन्य उपकरणों तक पहुंच मिली हुई थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक उसने इसका गलत फायदा उठाया।

सीक्रेट बेचने के बदले हजारों डॉलर मिलते थे : झाओ अपने निजी मोबाइल से सेना के गोपनीय दस्तावेजों की तस्वीरें खींचता था। इनमें सेना के ऑपरेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क, सैन्य अभ्यास और रॉकेट-मिसाइल सिस्टम से जुड़ी जानकारी थी। उसने रॉकेट सिस्टम से जुड़ी तकनीकी किताबों के कुछ हिस्से भी चीन से जुड़े लोगों को दिए। इसके अलावा उसने सेना के कंप्यूटर और सरकारी हार्ड ड्राइव बेचने की पेशकश भी की थी। जांच के मुताबिक, इस काम के बदले उसे



हजारों डॉलर मिले।

पूर्व सैनिक भी साजिश में शामिल : अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक यह साजिश 2021 के आखिर में शुरू हुई थी। इसमें रूयो डुआन नाम का एक पूर्व अमेरिकी सैनिक भी शामिल था। वह ओरेगन में रहता था। डुआन ने झाओ और सेना में काम कर रहे दूसरे सैनिकों को गोपनीय जानकारी देने के लिए तैयार किया था। वह चीन से जुड़े लोगों तक यह जानकारी पहुंचाने और सैनिकों को पैसे दिलाने का इंतजाम करता था। डुआन भी इस मामले में अपना जुर्म कबूल कर चुका है।

सीसीटीवी में तस्वीरें लेते दिखा, 17 लाख रुपए मिले जांच एजेंसियों ने सेना के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में झाओ को गोपनीय दस्तावेजों की तस्वीरें लेते देखा। इसके बाद 6 मार्च 2025 को उसे वॉशिंगटन के लेसी शहर में उसके घर से गिरफ्तार किया गया। घर की तलाशी में करीब 30 हजार डॉलर यानी लगभग 27 लाख रुपए नकद मिले। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान और सेना की कई हार्ड ड्राइव भी बरामद हुईं। झाओ को इस साजिश से 17 लाख रुपए मिले थे। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा- सैनिकों की सुरक्षा खतरे में डाली अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि झाओ ने सेना में मिली अपनी जिम्मेदारी का गलत इस्तेमाल किया। उसने पैसों के लिए गोपनीय जानकारी चीन से जुड़े लोगों को दी। सेना के काउंटर इंटेलिजेंस कमांड के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल सीन स्टिंचन ने कहा कि झाओ ने सेना की शपथ और अपने साथियों के भरोसे को तोड़ा। उसकी हरकत से सैनिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी।



रात के समय कार्बोहाइड्रेड चीजें खाने से बचें

शाम के पांच बजे के बाद कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए या नहीं? यदि वजन पर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो पांच नहीं सात बजे के बाद ऐसी चीजें खाने से बचें, जिनमें कार्बोहाइड्रेड होता है। रात के समय हमेशा ऐसी चीजें ही खाएं, जो आसानी से पच जाएं।

- केला और सेब लौह तत्वों से भरपूर हैं। इसलिए वह कटने के बाद भूरे हो जाते हैं। यह गलतफहमी है। भूरा होने की वजह आयरन नहीं एंजाइम हैं। रंग गहराने के पीछे फलों में मौजूद फिनॉलिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हैं, ये कंपाउंड हवा में तैरती ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रंग बदलते हैं।

लो फैट का दूध लें

- दूध और उससे बने उत्पाद बचपन बीत जाने के बाद उपयोगी नहीं। दूध और दूध से बने उत्पादों में केवल प्रोटीन ही नहीं आवश्यक एमिनो एसिड, फैटी एसिड तथा कैल्शियम के साथ विटामिन ए, डी तथा मैग्नीशियम, फास्फोरस व पोटेशियम भी होता है। दूध अवश्य लें भले ही वह लो फैट हो।
- खाने में डाले गए नमक से ज्यादा नुकसानदेह है, ऊपर से नमक डालना? नमक तैयार खाने में पहले से डाला गया हो या ऊपर से मिलाया गया, उसमें मौजूद सोडियम एक समान होता है।
- आयरन का बेहतर स्रोत होने के कारण पालक ही रक्त की कमी से बचाता है। बहुत सी पत्तेदार सब्जियों में भरपूर आयरन होता है जैसे, ब्रॉक्ली में 40 मि.ग्रा., चौलाई-20 मि.ग्रा., सरसों में 16-3 मि.ग्रा., गाजर की पत्तियों में 18 मि.ग्रा. आयरन होता है, जबकि पालक में 1.1 मि.ग्रा. होता है।
- सूजी अनाज नहीं है? सूजी मैदा का दानेदार रूप है। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा पॉलिश चावल और मैदे के समान होती है।

एक अंडा ही रोज खाएं

- शुगर फ्री उत्पाद हेल्दी होते हैं। आमतौर पर लोग अकसर शुगर फ्री उत्पादों को लो कैलोरी मान डायबिटीज और वजन नियंत्रण के लिए उपयोगी समझते हैं, परंतु ये शुगर फ्री उत्पाद अनेक अनदेखे शुगर स्रोतों से युक्त होते हैं। इनका अधिक सेवन स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है।
- अंडों में कोलेस्ट्रॉल अधिक होता है, इसलिए इसे नहीं खाना चाहिए। एक अंडे में 215 मि.ग्रा. कोलेस्ट्रॉल होता है, अकेले एक अंडे की जर्दी में 300 मि.ग्रा. कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन अंडे में अन्य पौष्टिक तत्वों की बहुलता है। हाल ही में हुई रिसर्च से पता चला कि जो लोग एक अंडा प्रतिदिन खाते हैं, उन्हें अंडा न खाने वालों की तुलना में हृदय रोग का खतरा कम होता है।
- उपवास रखने से शरीर के टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। उपवास संतुलित भोजन और अधिक कैलोरीज पर नियंत्रण रखता है, लेकिन इस दौरान रिच डाइट, फल, जूस, अधिक मेवे आदि लेने से इसका उलटा भी हो सकता है।

चीनी ज्यादा न खाएं

- चीनी खाने से डायबिटीज होती है। यह सोच कर चीनी न खाने पर डायबिटीज नहीं होगी, गलत है। स्टार्च, फैट, प्रोटीन और चीनी जैसे अधिक कैलोरी वाले खाद्य शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ाकर डायबिटीज को जन्म देते हैं। जब शरीर कार्बोहाइड्रेट को पचाने में अक्षम हो, तभी डायबिटीज होती है।
- शहद जैसे प्राकृतिक पदार्थ शुगर का विकल्प हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये शुगर फ्री तथा कम कैलोरी वाले प्राकृतिक स्रोत हैं तथा इन्हें रिफाइन भी नहीं किया जाता, इसलिए ये नुकसानदेह नहीं। लेकिन 1 चम्मच शहद में 65 कैलोरी तथा एक चम्मच शुगर में 46 कैलोरी होती है। ग्लाइस्मिक इंडेक्स भी शहद में 87 तथा शुगर में 59 होता है।
- बिना नमक का खाना तेजी से वजन कम करता है। याद रखें कि पहले तो सोडियम के न रहने पर पानी कम होता है न कि फैट। नर्वस सिस्टम सही ढंग से काम करे, इसके लिए भी सोडियम जरूरी होता है। इसका लेवल डिप्रेशन, स्वभाव परिवर्तन और कमजोरी का कारण होता है।
- शुगर मूड को प्रभावित करती है। इंसानी दिमाग ऊर्जा के लिए पूरे तौर पर ब्लड शुगर (ग्लूकोज) पर निर्भर रहता है। इसकी कमी से हाइपोग्लीमिया का दौरा तथा कमजोरी, डिप्रेशन, दिमागी गड़बड़ियां हो सकती हैं।

स्वास्थ्य सही है तो शरीर सही है। शरीर सही है तो मन सही है। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम आपको बताते हैं, हेल्थ के क्या लेना चाहिए और क्या नहीं।

केला-दूध फायदेमंद

- रात में मेटाबॉलिज्म सिस्टम धीमा होता है। इसलिए भारी नाश्ता करना चाहिए। सुबह का नाश्ता दिन भर की ऊर्जा के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन इसके लिए भारी की जरूरत नहीं। आप केले या दूध से भी काम चला सकती हैं।
- मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। ऐसा हमेशा नहीं होता। लेकिन कुछ स्थितियों में इसे मान लेना बेहतर होता है।
- बिना शुगर के फलों के जूस प्राकृतिक व शुगर फ्री होते हैं। ये लो कैलोरी जरूर होते हैं, लेकिन इसमें फ्रूकटोस होने के कारण शुगर फ्री नहीं होते।



आयुर्वेद से भगाएं ऑस्टियोआर्थराइटिस

आयुर्वेद में ऑस्टियोआर्थराइटिस को संधिवात के रूप में जाना जाता है, जो जोड़ों का विकार है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर के निचले हिस्से की हड्डियों को सपोर्ट देने वाले सुरक्षात्मक कार्टिलेज और कोमल ऊतकों का किसी कारणवश टूटना शुरू होना है।

इस हालत में किसी भी गतिविधि के बाद या आराम की लंबी अवधि के बाद जोड़ों का लचीलापन कम हो जाता है और वो सख्त हो जाते हैं और दर्ददायक बनते हैं।

ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए एलोपैथिक उपचार के अलावा, कुछ आयुर्वेदिक इलाज भी उपलब्ध हैं। आयुर्वेद कहता है कि शरीर में तीन जीव-ऊर्जा या दोष होते हैं, जो हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं। वात, कफ और पित्त यह उनके नाम हैं। जब एक व्यक्ति किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त होता है, तब यह इन दोषों में असंतुलन की वजह से होता है।

ऑस्टियोआर्थराइटिस वात दोष में एक असंतुलन के कारण होता है और इसलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए आयुर्वेदिक इलाज में इस दोष को संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिससे व्यक्ति को दर्द से राहत मिलने में आसानी होती है।

ये हैं जड़ीबूटी

- **गुग्गुल** : ऊतकों को मजबूत बनाता है।
- **त्रिफला** : विषैले तत्वों को शरीर से साफ करना।
- **अश्वगंधा** : शरीर और मन को आराम और तंत्रिका तंत्र को उत्तेजना देना।
- **कॅस्टर (एरंडी)** : इस तेल को दर्द होने वाले क्षेत्र में लगाने के साथ ही इसका सेवन भी लिया जा सकता है, क्योंकि यह एक प्रभावी औषधि है।
- **बाला** : शरीर में रक्त परिसंचरण को बढ़ाने के लिए, दर्द को कम करने के लिए, नसों को ठीक करता है एवं शरीर में ऊतकों का विकास होता है।
- **शालाकी** : अपने सूजन विरोधी गुणों के लिए और शरीर की हड्डियों के करीब के ऊतकों की मरम्मत करने में सक्षम होने के गुण के लिए उपयोगी है।

अनुलोम विलोम से स्वच्छ व निरोग रहती हैं नाड़ियां

अनुलोम का अर्थ होता है सीधा और विलोम का अर्थ है उल्टा। यहां पर सीधा का अर्थ है नासिका या नाक का दाहिना छिद्र और उल्टा का अर्थ है- नाक का बायां छिद्र। अर्थात अनुलोम-विलोम प्राणायाम में नाक के दाएं छिद्र से सांस खींचते हैं, तो बायीं नाक के छिद्र से सांस बाहर निकालते है।

यदि नाक के बाएं छिद्र से सांस खींचते हैं, तो नाक के दाहिने छिद्र से सांस को बाहर निकालते हैं। अनुलोम-विलोम प्राणायाम को कुछ योगीगण 'नाड़ी शोधक प्राणायाम' भी कहते हैं। उनके अनुसार इसके नियमित अभ्यास से शरीर की समस्त नाड़ियों का शोधन होता है यानी वे स्वच्छ व निरोग बनी रहती हैं। इस प्राणायाम के अभ्यासी को वृद्धावस्था में भी गठिया, जोड़ों का दर्द व सूजन आदि शिकायतें नहीं होतीं।

प्राणायाम की विधि

- अपनी सुविधानुसार पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन अथवा सुखासन में बैठ जाएं। दाहिने हाथ के अंगूठे से नासिका के दाएं छिद्र को बंद कर लें और नासिका के बाएं छिद्र से 4 तक की गिनती में सांस को भरें और फिर बायीं नासिका को अंगूठे के बगल वाली दो अंगुलियों से बंद कर दें। तत्पश्चात दाहिनी नासिका से अंगूठे को हटा दें और दायीं नासिका से सांस को बाहर निकालें।
- अब दायीं नासिका से ही सांस को 4 की गिनती तक भरे और दायीं नाक को बंद करके बायीं नासिका खोलकर सांस को 8 की गिनती में बाहर निकालें।
- इस प्राणायाम को 5 से 15 मिनट तक कर सकते हैं।

सावधानियां

- कमजोर और एनीमिया से पीड़ित रोगी इस प्राणायाम के दौरान सांस भरने और सांस निकालने (रेचक) की गिनती को क्रमश: चार-चार ही रखें। अर्थात चार गिनती में सांस का भरना तो चार गिनती में ही सांस को बाहर निकालना है।
- स्वस्थ रोगी धीरे-धीरे यथाशक्ति पूरक-रेचक की संख्या बढ़ा सकते हैं।
- कुछ लोग समयाभाव के कारण सांस भरने और सांस निकालने का अनुपात 1-2 नहीं रखते। वे बहुत तेजी से और जल्दी-जल्दी सांस भरते और निकालते हैं। इससे वातावरण में व्याप्त धूल, धुआं, जीवाणु और वायरस, सांस नली में पहुंचकर अनेक प्रकार के संक्रमण को पैदा कर सकते हैं।
- अनुलोम-विलोम प्राणायाम करते समय यदि नासिका के सामने आटे जैसी महीन वस्तु रख दी जाए, तो पूरक व रेचक करते समय वह न अंदर जाए और न अपने स्थान से उड़े। अर्थात सांस की गति इतनी सहज होना चाहिए कि इस प्राणायाम को करते समय स्वयं को भी आवाज न सुनाई पड़े।





रोजाना खाएं अदरक मिलेंगे अनगिनत फायदे

अदरक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेटस, आयरन, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। अदरक खाने से कई फायदे होते हैं।

अदरक एक भारतीय मसाला है जो हर घर में रोजाना इस्तेमाल होता है। इसकी तासीर गर्म होने के कारण इसका अधिकतर सेवन सर्दियों में किया जाता है। इस मौसम में अदरक खाने से खांसी- जुकाम, बलगम जैसी परेशानियों से बचा जा सकता है। अदरक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेटस, आयरन, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। अदरक खाने से कई फायदे होते हैं। आज हम उन्हीं फायदों के बारे में बताएंगे। चलिए जानते है एक टुकड़ा अदरक रोजाना खाने से शरीर को किस प्रकार फायदा मिलता है।

जी मिचलाना

जी मिचलना और उल्टी की समस्या को रोकने के लिए अदरक औषधि की तरह का काम करता है। 1 चम्मच अदरक के जूस में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं। इसको हर दो घंटे बाद पीएं। जल्द ही राहत मिलेगी।

गठिया दर्द में राहत

अदरक में एंटी-इन्फ्लॉमेट्री प्रॉपर्टीज होती है जो जोड़ों के दर्द को खत्म करने में सहायक है। अदरक को खाने से या इसका लेप लगाने से भी दर्द खत्म होता है। इसका लेप बनाने के लिए अदरक को अच्छे से पीस लें। उसमें हल्दी मिला लें। इस पेस्ट को दिन में दो बार लगाएं। कुछ ही दिनों में फर्क दिखाई देने लगेगा।

मासिक धर्म में फायदेमंद

कुछ महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान बहुत दर्द होती है। ऐसे में अदरक की चाय काफी फायदा पहुंचाती है। इसलिए दिन में 2 बार अदरक की चाय पीएं। इससे दर्द कम होगा।

सर्दी- जुकाम और फ्लू

सर्दियों के मौसम में सर्दी-जुकाम और फ्लू जैसी छोटी-मोटी समस्या होना आम है। इससे बचने के लिए नियमित रूप से अदरक का सेवन करें। यह शरीर को गर्म रखता है जिससे पसीना अधिक आता है और शरीर गर्म बना रहता है।

माइग्रेन का इलाज

जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है उनके लिए अदरक रामबाण है। जब भी माइग्रेन का अटैक आए, तब अदरक की चाय बना कर पीएं। इसको पीने से माइग्रेन में होने वाले दर्द और उल्टी से काफी हद तक राहत मिलेगी।

दिल को रखता है स्वस्थ

अदरक कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने, ब्लड प्रेशर को ठीक रखने, खून को जमने से रोकने का काम करता है। इससे दिल संबंधित बीमारियां भी नहीं होती है। इसलिए अपनी डाइट में अदरक को शामिल करें।

पाचन तंत्र मजबूत

अदरक पेट फूलने, कब्ज, गैस, एसीडिटी जैसी समस्याओं को ठीक रखने में भी सहायक है। जिन लोगों को पेट से संबंधित समस्याएं रहती है वह रोजान सुबह खाली पेट अदरक का सेवन करें।

मोर्निंग सिकनेस

मोर्निंग सिकनेस की समस्या अधिकतर गर्भवती महिलाओं को होती है। रोजाना सुबह अदरक के 1 टुकड़े को चबा कर खाएं। कुछ दिनों तक अदरक खाने से मोर्निंग सिकनेस की समस्या दूर हो जाएगी।

ऊर्जा करें प्रदान

सर्दियों में अदरक खाने से शरीर गर्म तो रहता ही है साथ ही उसे एनर्जी भी मिलती है। रोजाना सुबह अदरक वाली चाय पीने से शरीर में चुस्ती- फुर्ती बनी रहेगी।



एम्ब्लायोपिया स्थाई रूप से धुंधली हो सकती है दृष्टि

जिन बच्चों की आंखों की अश्रु नलिकाएं बचपन से ही अवरुद्ध होती हैं। उनकी दृष्टि धुंधली हो सकती है। यदि जन्म के बाद शुरुआती छह से 10 साल के अंदर इसका इलाज न कराया जाए तो दृष्टि स्थाई रूप से धुंधली हो सकती है। इस बीमारी को एम्ब्लायोपिया या लेजी आई कहते हैं।

तीन साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनमें अश्रु नलिकाएं (नैसोलेक्रिमल डक्ट ऑब्सट्रक्शन-एनएलडीओ) अवरुद्ध होती हैं। उनमें एम्ब्लायोपिया बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। इनमें से छह प्रतिशत मरीज ऐसे होते हैं, जिनमें जन्म से ही यह परेशानी होती है।

रखें सावधानी

पेंसिलवेनिया के लैनकास्टर के फैमेली आई ग्रुप के अध्ययनकर्ता नोएल एस. मैटा व डेविड आई. सिलबर्ट का कहना है कि अध्ययन में शामिल 375 बच्चों में से 22 प्रतिशत बच्चों में एम्ब्लायोपिया के खतरे के कारक थे। सामान्य आबादी में इस बीमारी की आठ गुना की दर से वृद्धि हो रही है।

जन्मजात बीमारी

मैटा का कहना है, हमने एनएलडीओ की जन्मजात परेशानी वाले सभी बच्चों की जांच की बात कही। हमने सावधानीपूर्वक उनमें एम्ब्लायोपिया के खतरे के कारकों की मौजूदगी का अध्ययन किया।

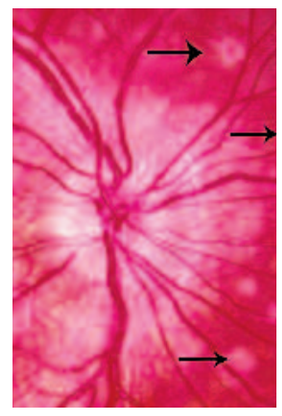

उत्तरकाशी अग्निकांड: सीएम धामी पहुंचे पवानी गांव, ग्रामीणों से मिले

उत्तरकाशी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोरी तहसील के अग्निकांड प्रभावित पवाणी गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और अग्निकांड से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं और जरूरतें सुनीं। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक प्रभावित परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करते हुए भरोसा दिलाया कि इस मुश्किल घड़ी में राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अग्निकांड से हुए नुकसान का वास्तविक आकलन कर प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाए। कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता प्रभावित परिवारों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना और उनका जीवन सामान्य करना है। सर्दी



के मौसम और संभावित बर्फबारी को देखते हुए अधिकारियों को ऐसी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए, जिससे किसी भी परिवार को प्रतिकूल मौसम में परेशानी न हो। कहा कि अग्निकांड में ग्रामीणों के घरों के साथ ही छह माह का सुरक्षित रखा राशन भी नष्ट हो गया है। ऐसे में प्रभावित परिवारों को आगामी छह माह तक राशन उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही उनकी दैनिक जरूरतों का भी विशेष ध्यान रखा जाए। बच्चों की शिक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निकांड के कारण किसी भी बच्चे की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यकतानुसार विद्यालय और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित परिवारों के बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की जरूरतों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों ने इस भीषण अग्निकांड में अपने आशियाने और जीवनभर की जमा पूंजी खोई है, उनकी पीड़ा को समझना बेहद कठिन है। सरकार का पूरा तंत्र प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा है। यह केवल आर्थिक सहायता देने का विषय नहीं है, बल्कि प्रत्येक परिवार को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने और उनके जीवन में विश्वास व उम्मीद लौटाने का प्रयास है।

दुपहिया वाहन चोरों के निशाने पर, स्कूटी और बाइक चोरी

देहरादून। राजधानी में दुपहिया वाहन चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चोरों ने अलग–अलग स्थानों से तीन दुपहिया वाहन चोरी कर लिए। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित थानों में मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, शिवालिक लालतप्पड़ निवासी विजय भारती सलवान ने डोईवाला कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई कि वह मान ढाबे पर खाना खाने गया था। उसने अपनी स्कूटी ढाबे के बाहर खड़ी की थी। कुछ देर बाद वापस लौटने पर स्कूटी गायब मिली। वहीं, मोहनपुर प्रेमनगर निवासी सुंदर कुमार ने पटेलनगर कोतवाली में शिकायत दी कि उनकी मोटरसाइकिल आईएसबीटी फ्लाईओवर के नीचे से चोरी हो गई। इसी तरह मेहबूब कॉलोनी निवासी मोहम्मद शहजाद की मोटरसाइकिल घर के बाहर से चोरी कर ली गई। पुलिस ने तीनों मामलों में मुकदमे दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

चोपता बाजार में घंटों लग रहा जाम

चोपता। तल्लानागपुर के मुख्य बाजार चोपता में इन दिनों यातायात व्यवस्था पटरी से उतरती नजर आ रही है। यहां घंटों तक लगने वाला जाम लग रहा है। वाहनों की लंबी कतारें लगने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानियों हो रही है। यातायात व्यवस्था होमगार्ड के भरोसे संचालित है। इससे कार्तिक स्वामी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों व स्थानीय लोगों को दिक्कते हो रही है। यहां दर्जनों गांवों के लोग दैनिक कार्यों के लिए आते है। यातायात व्यवस्था को होमगार्ड के जवान नियंत्रित करने के प्रयास करते है।

जाम से कार्तिक स्वामी मंदिर जाने वाले श्रद्धालु घंटों जाम खुलने का इंतजार करते है। क्षेत्र पंचायत सदस्य फलासी दिनेश सिंह नेगी ने बताया कि घंटों तक जाम लगने से स्थानीय जनता, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों को परेशान होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि चोपता में यातायात व्यवस्था के लिए नियमित पुलिस कर्मियों की तैनाती की मांग की है। व्यापारी मानवेन्द्र सजवाण ने कहा कि जाम की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। यातायात व्यवस्था केवल होमगार्ड के भरोसे छोड़ने से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने प्रशासन से पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित करने की मांग की। व्यापारी विनोद जगवाण बताया कि यदि समय रहते चोपता की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया तो आने वाले समय में वाहनों का बढ़ता दबाव स्थानीय जनता के साथ ही तीर्थाटन एवं पर्यटन के लिए चुनौती बन सकता है।

स्मैक तस्करी में तीन गिरफ्तार, 31.60 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद

देहरादून। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अलग–अलग थाना क्षेत्रों से तीन लोगों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से कुल 31.60 ग्राम स्मैक बरामद की गई। पुलिस ने तीनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, क्लेमेनटाउन थाना पुलिस ने आशारोड़ी बैरियर के पास एक युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते देखा। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो वह भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा कर उसे दबोच लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 10.87 ग्राम स्मैक बरामद हुई। आरोपी की पहचान आशीष अग्रवाल उर्फ चाईनीज, पुत्र सर्वेश कुमार, निवासी मोहब्बेवाला के रूप में हुई।

दूसरी कार्रवाई में पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने पुराना ट्यूबवेल चंदाताल के पास एक स्कूटी सवार को रोककर तलाशी ली। उसके कब्जे से 11.41 ग्राम स्मैक बरामद हुई। आरोपी की पहचान मोहसिन, पुत्र अनवर राव, निवासी बड़ी मस्जिद के पास बड़ोवाला के रूप में हुई। वहीं, विकासनगर कोतवाली पुलिस ने आसन बैराज के पास बिलाल, पुत्र इस्लाम, निवासी कुंजा ग्रांट को गिरफ्तार किया। उसके पास से 9.32 ग्राम स्मैक बरामद की गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मामले में स्कूटी को भी सीज कर दिया।

दो बाइकों की आमने–सामने भिड़ंत, उपचार के दौरान युवक की मौत

एसबीआई मुख्य शाखा के पास हुआ हादसा, तेज रफ्तार बाइक सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

देहरादून। सहसपुर क्षेत्र में दो मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

नए भवन की स्वीकृति का प्रस्ताव पारित

देवाल। बहुउद्देशीय सहकारी समिति की सामान्य निकाय की बैठक में सदस्यों ने समिति के पुराने जीर्ण–शीर्ण भवन की मरम्मत और नए भवन की स्वीकृति की मांग की। इस संबंध में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक समिति के अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा की अध्यक्षता में हुई। सदस्यों ने बताया कि भवन कई बार प्रस्ताव भेजने के बाद भी स्वीकृत नही हुआ है। समिति ने वित्त वर्ष 2025–26 में तीन करोड़ 17 लाख रुपये का व्यवसाय किय जिससे 7.82 लाख रुपये का लाभ हुआ। वित्त वर्ष 2026–27 में समिति ने 87 लाख रुपये का शून्य प्रतिशत ऋण वितरित किया और 40 लाख रुपये की ऋण वसूली की। समिति किसानों से 52 रुपये प्रति किलो की दर से मडुआ खरीदने की भी तैयारी में है। बैठक में सहकारी बैंक के प्रबंधक मुकेश पाठक, सुरेंद्र बिष्ट, खड़क सिंह, समिति के संचालक मंडल के सदस्य मंजू देवी, सुमन देवी, देवकी देवी, त्रिभुवन सिंह आदि मौजूद रहे।

सड़कों पर उतरा कांग्रेस का जनसैलाब

देहरादून। प्रदेश में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को शक्ति प्रदर्शन किया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने लोकभवन की ओर कूच किया। इस दौरान हाथीबड़कला चौकी के समीप पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता राजपुर रोड स्थित प्रदेश मुख्यालय में एकत्र हुए। यहां से जुलूस के रूप में कांग्रेस भवन से राजपुर रोड, दिलाराम बाजार और सालावाला होते हुए हाथीबड़कला की ओर रवाना हुए। प्रदर्शनकारियों की योजना भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेशभर में चलाए गए हस्ताक्षर अभियान के दस्तावेज राज्यपाल को सौंपने की थी।

कांग्रेस ने 10 से 23 नवंबर तक प्रदेश के सभी जिला, ब्लॉक और महानगर मुख्यालयों में हस्ताक्षर अभियान चलाया था। इस अभियान के



तहत बड़ी संख्या में लोगों से हस्ताक्षर कराकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जनसमर्थन जुटाने का प्रयास किया गया। हस्ताक्षरयुक्त बैनर और पोस्टर एकत्र कर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचाए गए थे। हाथीबड़कला में पुलिस द्वारा रोके जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने का प्रयास किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। इससे मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। समाचार लिखे जाने तक पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच खींचतान जारी थी।

संक्षिप्त समाचार

सरकारी कामकाज को हाईटेक बनाने की तैयारी

देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी कामकाज को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार ने पहल तेज कर दी है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने शासकीय कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के अधिकाधिक इस्तेमाल पर जोर देते हुए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को इसके लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि वर्तमान समय में एआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में उत्तराखंड में भी इस तकनीक की संभावनाओं का लाभ उठाया जाना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों की कार्यप्रणाली के अनुरूप एआई टूल्स के व्यावहारिक उपयोग की संभावनाएं तलाशने और सरकारी कार्यों में इनके इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने को कहा।

एआई के प्रभावी इस्तेमाल के लिए बनेगी टास्क फोर्स

मुख्य सचिव ने प्रदेश में एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तत्काल टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन के विभिन्न कार्यों में इस तकनीक की उपयोगिता को देखते हुए इसके व्यापक इस्तेमाल की दिशा में व्यवस्थित प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए विभागों की जरूरतों के अनुसार तकनीकी समाधान विकसित करने पर भी ध्यान दिया जाए।

वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भाजपा ने खोला चुनावी मोर्चा

देहरादून। उत्तराखंड में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संगठनात्मक तैयारियों को गति देनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में गुरुवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय को विधिवत प्रदेश चुनाव कार्यालय के रूप में संचालित करने की शुरुआत की गई। प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम माधव, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार, हवन और विधि–विधान से पूजा–अर्चना कर चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कार्यालय परिसर को सरकार और संगठन की उपलब्धियों एवं कार्यों से संबंधित सामग्री से सजाया गया। हवन–पूजन में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने आहुतियां देकर प्रदेश की सुख–समृद्धि तथा आगामी चुनावी अभियान के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम में प्रदेश सह प्रभारी अरविंद मेनन, प्रदेश महामंत्री संगठन फणींद्रनाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार, दीप्ति रावत, तरुण बंसल, प्रदेश कार्यालय सचिव जगमोहन रावत सहित सरकार में दायित्वधारी, वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

658 किमी की एमटीबी रेस ने दिया उत्तराखण्ड की एकता का संदेश

मसूरी। उत्तराखण्ड में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के साथ प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिल रही है। ऐसे आयोजन न केवल साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहित कर रहे हैं, बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों में शीतकालीन पर्यटन और स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ा रहे हैं। यह बात कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गुरुवार को मसूरी नगर पालिका के टाउन हॉल में आयोजित अल्टीमेट उत्तराखण्ड हिमालयन एमटीबी चैलेंज–2026 के समापन समारोह में कही।

कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने प्रतियोगिता के विजेताओं को ट्रॉफी और पदक देकर सम्मानित किया। साथ ही सभी प्रतिभागियों को स्मृति चिह्न भेंट किए। उन्होंने साइकिलिस्टों के साहस, उत्साह और खेल भावना की सराहना करते हुए सभी को बधाई दी। गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखण्ड प्राकृतिक सौंदर्य और चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों के कारण साहसिक खेलों के लिए अनुकूल गंतव्य है। राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित इस प्रतियोगिता में देशभर के साइकिलिस्टों ने कुमाऊं से गढ़वाल तक 658 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रदेश की एकता और सांस्कृतिक जुड़ाव का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन प्रदेश के कम चर्चित पर्यटन स्थलों को भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

संविधान में निर्धारित समय-सीमाओं और मूल संकल्पों की समीक्षा जरूरी : विनोद नौटियाल

संविधान संशोधन के साथ जनता के प्रति जवाबदेही और मूल भावना का संरक्षण भी आवश्यक

जयन्त प्रतिनिधि। देहरादून : संविधान में निहित मूल प्रावधानों, निर्धारित समय-सीमाओं और उनके अनुपालन को लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पूर्व अपर महाधिवक्ता एवं उप महाधिवक्ता अधिवक्ता विनोद नौटियाल ने केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत संवैधानिक प्रतिवेदन भेजकर संविधान निर्माताओं द्वारा तय किए गए संकल्पों और समय-सीमाओं की समीक्षा कराने तथा इस विषय पर संसद में व्यापक चर्चा कराने की मांग की है।नौटियाल ने अपने प्रतिवेदन में सवाल उठाया है कि आजादी के करीब आठ दशक बाद भी संविधान के कई ऐसे प्रावधान हैं, जिनमें निर्धारित समय-सीमाओं और उद्देश्यों के अनुरूप अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन के माध्यम से प्रावधानों में बदलाव तो किए गए, लेकिन उनके मूल उद्देश्यों और समय-सीमाओं के पालन का समुचित मूल्यांकन भी होना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से भाषा संबंधी संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि अनुच्छेद 343 में अंग्रेजी के प्रयोग को 26 जनवरी 1965 तक सीमित रखने की व्यवस्था की गई थी, जबकि अनुच्छेद 348 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी के प्रयोग को लेकर प्रावधान किए गए थे। इसके बावजूद न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में भारतीय भाषाओं के व्यापक उपयोग और आम नागरिकों को उनकी भाषा में न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में अपेक्षित प्रयासों की समीक्षा जरूरी है। उन्होंने अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए किए गए कार्यों और भविष्य की रणनीति पर भी संसद में विचार करने का आग्रह किया। प्रतिवेदन में राजनीतिक आरक्षण की अवधि का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया है। नौटियाल के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 334 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राजनीतिक आरक्षण की प्रारंभिक अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में लगातार संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से बढ़ाया जाता रहा। वर्ष 1959 से 2019 के बीच सात संशोधनों के जरिए इसकी अवधि बढ़ाकर 80 वर्ष तक कर दी गई। उन्होंने सवाल किया कि इस अवधि के विस्तार से पहले क्या पर्याप्त आंकड़ों, सार्वजनिक रिपोर्टों और संसदीय समीक्षा के आधार पर निर्णय लिया गया था।

सरकारी सेवाओं में आरक्षण पर पुनर्विचार की आवश्यकता

उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पूर्व अपर महाधिवक्ता एवं उप महाधिवक्ता अधिवक्ता विनोद नौटियाल ने सरकारी सेवाओं में आरक्षण के विषय पर भी उन्होंने व्यापक पुनर्विचार की आवश्यकता जताई। उनका कहना है कि अनुच्छेद 16 में आरक्षण के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन इस व्यवस्था की निरंतर समीक्षा और सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन होना चाहिए। उन्होंने मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य (2020) तथा जनहित अभियान बनाम भारत सरकार (2023) के निर्णयों का उल्लेख करते हुए आरक्षण से जुड़े संवैधानिक और कानूनी पहलुओं पर चर्चा की मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था पर आर्थिक स्थिति को भी प्रमुख आधार बनाकर विचार किया जाना चाहिए, ताकि सभी वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को समान अवसर मिल सकें।

ग्वास गांव में कार्तिकेय जन्मोत्सव महोत्सव 14 से

चोपता। तल्लानागपुर की ग्राम पंचायत घिमतोली के ग्वास गांव में छठवें त्रिदिवसीय कार्तिकेय जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आगामी 14 से 16 दिसम्बर तक आयोजन होगा। मुख्य आकर्षण 15 दिसम्बर को निकाली जाने वाली भगवान कार्तिकेय की भव्य झांकी होगी।

आयोजन के लिए गांव में साफ–सफाई, सजावट, श्रद्धालुओं के स्वागत तथा धार्मिक कार्यक्रमों की तैयारियां की जा रही हैं। भाजपा चोपता मंडल अध्यक्ष अर्जुन सिंह नेगी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी को अपनी धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर मिलता है।

वन पंचायत सरपंच धर्मेन्द्र सिंह नेगी ने बताया कि ग्वास गांव में होने वाला कार्तिकेय जन्मोत्सव क्षेत्र की सामूहिक आस्था का उत्सव है।

जनसंवाद में उठा स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा

चकराता। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) चकराता के तत्वावधान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) दसऊ में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जनसंवाद आयोजित किया गया। इसमें ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, पेयजल की गुणवत्ता, पोषण आहार और शिक्षा से जुड़ी समस्याएं उठाते हुए विभागीय अधिकारियों से समाधान की मांग की।

ग्राम पंचायत गबेला के प्रधान मातबर शर्मा ने क्षेत्र में आपातकालीन चिकित्सा सुविधा के लिए 108 एंबुलेंस सेवा शुरू करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि कई बार लिखित मांग किए जाने के बावजूद क्षेत्र में यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। उन्होंने पीएचसी दसऊ का उच्चीकरण करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

बैठक में क्षेत्र में पथरी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए पेयजल स्रोतों की वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की गई। इस पर चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विपिन सिंह तोमर ने पेयजल विभाग को लिखित रूप से अवगत कराने और जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। इसके अलावा बाल विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन और बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार की गुणवत्ता सुधारने का मुद्दा भी उठा।

देश की एकता, अखंडता बनाए रखने की ली शपथ

कर्णप्रयाग/गौचर। डॉ. शिवानंद नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग में संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय संविधान के निर्माण में डॉ. भीमराव आंबेडकर की भूमिका विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छात्र–छात्राओं ने डॉ. आंबेडकर के विचारों, संविधान सभा में उनकी भूमिका तथा सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता के प्रति उनके योगदान पर विचार प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता में सुनील ने प्रथम, अंकित ने द्वितीय तथा महक अंसारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर डॉ. मिश्रा, डॉ. चंद्रमोहन जनस्वाण, डॉ. कविता डॉ. कीर्तिराम डंगवाल, डॉ. मदन लाल आदि मौजूद रहे। वही गौचर में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जीजीआईसी, जीआईसी, राजकीय पॉलीटेक्निक, सरस्वती शिशु मंदिर सहित निजी और सरकारी स्कूलों में भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने पर संवाद और परिचर्चा की गई।

अंकिता की निजी चौट सार्वजनिक करने के मामले में जीरो एफआईआर दर्ज

खुद का नाकी टेस्ट कराने की जताई इच्छा

देहरादून। अंकिता भंडारी की निजी व्हाट्सएप चौट सार्वजनिक किए जाने के विवाद ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। इस मामले में जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद गुरुवार को आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य थाना राजपुर पहुंचे। उन्होंने पुलिस के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही कहा कि यदि उनके खिलाफ आरोपों के आधार पर मामला बनता है तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। विनोद आर्य ने स्वयं नाकी टेस्ट कराने की इच्छा जताते हुए अंकिता के माता–पिता और आरोप लगाने वाले अन्य लोगों का भी नाकी टेस्ट कराने की मांग की। मामले की शुरुआत तब हुई जब अंकिता भंडारी के माता–पिता ने 25 नवंबर को देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंचकर अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) से मुलाकात की। उन्होंने विनोद आर्य और उनके अधिवक्ता अनुज पुंडीर के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि अंकिता की निजी व्हाट्सएप चौट सार्वजनिक की गई है। शिकायत के आधार पर थाना राजपुर में दोनों के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई। बाद में मामले को जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए हरिद्वार नगर कोतवाली स्थानांतरित कर दिया गया। अंकिता के माता–पिता पिछले कई दिनों से इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने थाना राजपुर में भी शिकायत दी थी, लेकिन मामला हरिद्वार से संबंधित होने के कारण वहां प्राथमिकी दर्ज किए जाने की बात कही गई थी। इससे निराश होकर बुधवार को अंकिता के माता–पिता गांधी पार्क में धरने पर बैठ गए। बाद में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ वे पुलिस मुख्यालय पहुंचे और शिकायत पर मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई। जीरो एफआईआर दर्ज होने की जानकारी मिलने के बाद गुरुवार को विनोद आर्य स्वयं थाना राजपुर पहुंचे।

सुशीला तिवारी अस्पताल में डीएम का औचक निरीक्षण

नैनीताल। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और मरीजों को हो रही परेशानियों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।

लगातार मिल रही शिकायतों के बीच जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। डीएम के अचानक पहुंचने से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में गंदगी, रैन बसेरे की अव्यवस्थित स्थिति और मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाओं में खामियां मिलने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। जिलाधिकारी ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर मरीजों से सीधे बातचीत की और उन्हें मिल रही चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली। सर्जरी वार्ड में निरीक्षण के दौरान मरीजों के



लिए लगाए गए बेड की हालत बेहद खराब मिली। कई बेड के गद्दे फटे हुए थे। इस पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अस्पताल प्रशासन को तत्काल बेड दुरुस्त कराने के निर्देश दिए, ताकि मरीजों को उपचार के दौरान किसी तरह की असुविधा न हो। निरीक्षण के दौरान मरीजों को अस्पताल से बाहर की दवाइयां लिखे जाने की शिकायत भी सामने आई। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि अस्पताल में उपलब्ध दवाइयों और चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर मिलना चाहिए। मरीजों को अनावश्यक रूप से बाहर से दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। डीएम ने रैन बसेरे की व्यवस्थाओं में सुधार करने के साथ ही अस्पताल परिसर में नियमित साफ–सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को सभी व्यवस्थाएं तत्काल दुरुस्त करने और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले किसी भी मरीज को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और व्यवस्थागत खामियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जयन्त

संस्थापक : नरेन्द्र उनियाल

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक नागेन्द्र उनियाल द्वारा प्रतिभा प्रेस बदरीनाथ मार्ग, कोटद्वार गढ़वाल (उत्तराखण्ड) से मुद्रित तथा बदरीनाथ मार्ग, कोटद्वार गढ़वाल (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित।

सभी विवादों का न्याय क्षेत्र कोटद्वार, (गढ़वाल) उत्तराखण्ड होगा।

CONT. 9412081969

PRGI NO. 35469/79

चैंपियंस लीगः लिवरपूल ने दर्ज की धमाकेदार जीत

मैनचेस्टर यूनाइटेड और स्पोर्टिंग सीपी का मुकाबला 2-2 से रहा ड्रॉ

नई दिल्ली (एजेंसी)। चैंपियंस लीग में लिवरपूल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए क्लब ब्रुग को 3-0 से हराया। इस मैच में अलेक्जेंडर इसाक ने दो गोल किए, जबकि फ्लोरियन विर्ट्ज ने भी एक शानदार लॉन्ग-रेंज गोल दागा। जान ब्रेयडेल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले की शुरुआत में ही अलेक्जेंडर इसाक ने करीब से गोल करके लिवरपूल को बढ़त दिला दी। लिवरपूल का डिफेंस भी मुकाबले में काफी मजबूत नजर आया और मैच के अंत में फ्लोरियन विर्ट्ज और इसाक के बेहतरीन गोलों की मदद से 3 अंक पक्के कर लिए। डोमिनिक सोबोस्जलाई के पास पर इसाक ने गोल करके लिवरपूल को हाफ-टाइम तक बढ़त दिला दी। इस दौरान यान सोमर ने हंगरी के खिलाड़ी सोबोस्जलाई के करीब से लिए गए शॉट को रोक दिया, जबकि दूसरे हाफ में लिवरपूल के गोलकीपर एलिसन बेकर ने फेलिक्स लेमारेचल के शॉट को बाहर कर दिया।



मैच खत्म होने से 11 मिनट पहले रियो न्गुमोहा के पास पर विर्ट्ज ने गेंद को पोस्ट के सहारे गोल में बदल दिया। इसके बाद, एलिसन की लंबी पास पर इसाक ने शानदार तरीके से गेंद को कंट्रोल करते हुए एक और गोल दागा। एंडोनी इराओला की टीम ने लीग चरण में अब तक 15 में से 12 अंक हासिल कर लिए हैं। उनका अगला मुकाबला घरेलू मैदान पर एफसी पोर्टो के खिलाफ होगा।

बार्सिलोना ने सबाह एफके को 4-1 से हराया, पीएसजी-रोमा के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा मुकाबला

नई दिल्ली (एजेंसी)। एफसी बार्सिलोना ने बाकू में सबाह एफके को 4-1 से हराया। एंथनी गॉर्डन के दो गोल और करीम अदेयेमी तथा गेब्रियल जीसस के एक-एक गोल की मदद से बार्सिलोना ने यूईएफए चैंपियंस लीग के लीग चरण में अपने पांचवें मैच में चौथी जीत दर्ज की। शुरुआत से ही गेंद पर अपना दबदबा बनाए रखने के बावजूद, बार्सिलोना को अजरबैजानी टीम के अनुशासित डिफेंस को भेदने में शुरुआती संघर्ष करना पड़ा। हाफ-टाइम के बाद, गेब्रियल जीसस के शॉट को पोकातिलोव ने रोका, लेकिन गेंद रिबाउंड होकर गॉर्डन के पास आई, जिन्होंने बार्सिलोना के लिए पहला गोल दागा। इसके बाद करीम अदेयेमी ने दूसरा गोल किया। जीसस ने तीसरा गोल किया, जबकि जॉय-लांस मिकल्स ने एक शानदार फिनिश के साथ अपनी टीम के लिए एक गोल किया। अदेयेमी पांचवां गोल करने के करीब थे, लेकिन पेनल्टी एरिया के अंदर से लगाया गया उनका जोरदार शॉट क्रॉसबार से टकरा गया। हालांकि, बार्सिलोना ने तीन महत्वपूर्ण अंक हासिल करने और राउंड ऑफ 16 में सीधे क्वालिफिकेशन की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ाने के लिए पर्याप्त काम कर लिया था। इस बीच, पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) ने अपने घरेलू मैदान पर एएस रोमा के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर यूईएफए चैंपियंस लीग में अपना अजेय रिकॉर्ड बरकरार रखा। मारियो हर्मोसो (5वें मिनट) के शुरुआती गोल के जवाब में इल्या जबार्नी (31वें मिनट) ने पीएसजी के लिए अपना पहला कॉन्टिनेंटल गोल किया।



ईयर एंडर 2026

टी20 विश्व कप का खिताब, छक्कों का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के लिए साल 2026 बेमिसाल रहा। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया अपनी ही धरती पर टी20 विश्व कप के खिताब का बचाव करने वाली दुनिया की पहली टीम बनी। इसके साथ ही एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल के अलावा टीम ने छक्कों का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। टी20 विश्व कप का खिताब : भारतीय टीम ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टी20 विश्व कप 2026 का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराने के साथ ही भारत टी20 विश्व कप के खिताब का बचाव करने वाला पहला देश बना। इसके साथ ही अपनी घरेलू सरजमीं पर टीम इंडिया चैंपियन बनने वाली पहली



टीम भी बनी। भारत ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। भारतीय टीम का प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में शानदार रहा और टीम को सिर्फ एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। भारत के लिए संजू सैमसन ने सर्वाधिक 321 रन बनाए जबकि 8 मैचों में 14 विकेट लेकर बेस्ट गेंदबाज रहे। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल : जापान की धरती पर खेले गए एशियन गेम्स 2026 में भी भारतीय क्रिकेट टीम का जलवा रहा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया। टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन ईशान किशन ने बनाए जबकि अक्षर पटेल सबसे सफल गेंदबाज रहे।

मुल्डर की शानदार गेंदबाजी, बांग्लादेशी बल्लेबाजों का दूसरी इनिंग में भी 'सरेंडर'

साउथ अफ्रीका ने एक पारी और 219 रनों से जीता दूसरा टेस्ट

सेंचुरियन(एजेंसी)। साउथ अफ्रीका ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट मैच में एक पारी और 219 रनों से हराया। सुपरस्पोर्ट्स पार्क के मैदान पर बांग्लादेश के बल्लेबाजों का प्रदर्शन दूसरी इनिंग में भी निराशाजनक रहा और पूरी टीम सिर्फ 184 रन बनाकर सिमट गई। दूसरी पारी में बांग्लादेश तंजीद हसन तमीम और महफिजुल इस्लाम ने सधी हुई शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 58 रन जोड़े। तंजीद 29 रन बनाकर आउट हुए, जबकि महफिजुल 38 रन बनाने के बाद पवेलियन लौटे। मोमिनुल हक अपना खाता भी नहीं



खोल सके। वहीं, कप्तान नजमुल हुसैन शांतो 34 रन बनाने के बाद वियान मुल्डर का शिकार बने। तौहीद हिरदॉय भी अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके और 33 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हुए। लिटन दास ने 15 रन बनाए, जबकि जेकर अली 2 रन ही बना सके। शोरिफुल इस्लाम (0) और तस्कीन अहमद (10 रन) भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। खलील अहमद 5 रन बनाकर आउट हुए। दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका की तरफ से वियान मुल्डर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 11 ओवर के स्पेल में 31 रन देकर 7 विकेट चटकाए, जबकि मार्को जानसेन ने 2 विकेट अपने नाम किए। कगिसो रबाडा ने एक विकेट झटका। बांग्लादेश की पूरी टीम पहली पारी में सिर्फ 91 रन बनाकर ढेर हो गई थी, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट खोकर 494 रन बनाने के बाद अपनी पारी को घोषित किया था।

न्यूजीलैंड-भारत दूसरा टेस्ट क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल में कैसा है भारत का टेस्ट रिकॉर्ड, 2020 में करना पड़ा था करारी हार का सामना

क्राइस्टचर्च में दूसरा टेस्ट आज से



नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेला जाना है। वेलिंगटन में खेला गया सीरीज का पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। आइए आपको बताते हैं कैसा रहा है टीम इंडिया का हेगली ओवल के मैदान पर टेस्ट रिकॉर्ड। दरअसल, भारतीय टीम ने क्राइस्टचर्च के इस मैदान पर अब तक सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेला था और इस मुकाबले में टीम को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। 2020 में विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम पहली पारी में 242 रन बनाकर ऑलआउट हुई थी।

इसके जवाब में भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड की पहली पारी को 235 रनों पर समेटने में सफल रहे थे। दूसरी पारी में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने आसानी से न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के आगे घुटने टेक दिए थे और पूरी टीम महज 124 रन बनाकर सिमट गई थी। न्यूजीलैंड ने 132 रनों के लक्ष्य को 3 विकेट खोकर हासिल करते हुए टेस्ट मैच को तीसरे ही दिन अपने नाम कर लिया था। हालांकि, शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम इस बार पिछली हार का हिसाब चुकता करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। न्यूजीलैंड ने इस ग्राउंड पर अब तक कुल 15 टेस्ट मैच खेले हैं और टीम को 9 में जीत हासिल हुई है। हेगली ओवल में न्यूजीलैंड को 4 टेस्ट मैचों में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। भारतीय टीम के लिहाज से पहला टेस्ट मैच शानदार रहा था। भारत का बल्लेबाजी क्रम जबरदस्त फॉर्म में नजर आया था। केएल राहुल और ऋषभ पंत शतकीय पारियां खेलने में सफल रहे थे, तो यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल और कप्तान गिल ने भी अर्धशतकीय पारियां खेली थीं।

भारतीय टीम पहली पारी में ही 720 रन बनाने में सफल रही थी, जो न्यूजीलैंड की धरती पर टेस्ट में बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर था। हालांकि, भारतीय टीम के गेंदबाज दूसरी पारी में संघर्ष करते हुए जरूर दिखाई दिए थे। टीम के गेंदबाज आखिरी दो सेशन में सिर्फ एक ही विकेट निकालने में सफल रहे थे और न्यूजीलैंड टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने में कामयाब रहा था।

दो बार शून्य पर आउट हुए लाथम, बुमराह ने दोनों पारियों में किया था शिकार, क्या निकाल पाएंगे तोड़?

क्राइस्टचर्च (एजेंसी)। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह का सामना करना आसान नहीं है। भारत के तेज गेंदबाज ने सीरीज के पहले टेस्ट की दोनों पारियों में उन्हें खाता भी नहीं खोलने दिया था। इसके बावजूद लाथम दूसरे टेस्ट में अपनी बल्लेबाजी की शैली में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना चाहते हैं। उनका कहना है कि उनकी तैयारी पिछले सप्ताह जैसी ही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट शुक्रवार से क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल में खेला जाएगा। बुमराह की अनूठी गेंदबाजी शैली और बल्लेबाज के करीब गेंद डालने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। स्विंग के अनुकूल परिस्थितियों में उनका सामना करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।





अपनी बल्लेबाजी में बदलाव नहीं करना चाहते लाथम

लाथम अपनी बल्लेबाजी शैली पर ही कायम रहना चाहते हैं। उनका मानना है कि तकनीक में बदलाव करने के बजाय अपने विचारों में स्पष्टता रखना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा, 'कभी-कभी मुश्किल यह होती है कि अगर कुछ अलग करने की कोशिश सफल नहीं होती, तो इससे ध्यान भटक जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आज मैं इस मुकाम पर हूं तो इसका कारण यही है कि मैं जो कर रहा हूं, उसे लेकर पूरी तरह स्पष्ट हूं।' लाथम ने कहा, 'तकनीक के मामले में इसे बिल्कुल सरल रखना सबसे महत्वपूर्ण है। चुनौती यह हो सकती है कि उस सोच से बाहर निकलकर रन बनाने का कोई जादुई तरीका खोजने की कोशिश की जाए। लेकिन हमारे खेल में ऐसा कोई जादुई तरीका नहीं है।'

बुमराह की गेंदबाजी शैली को बताया चुनौतीपूर्ण

दूसरे टेस्ट की पूर्व संध्या पर लाथम ने बुमराह की गेंदबाजी पर बात की। उन्होंने कहा, 'जसप्रीत बुमराह निश्चित रूप से चुनौती पेश करते हैं, चाहे वह नई गेंद से गेंदबाजी कर रहे हों या पुरानी गेंद से। उनकी गेंदबाजी शैली अनूठी है और वह दूसरे गेंदबाजों की तुलना में गेंद को बल्लेबाज के थोड़ा अधिक करीब डालते हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण उस गेंद को खेलने के लिए खुद को तैयार रखना है, जो सबसे खतरनाक साबित हो सकती है। हो सकता है कि कुछ खिलाड़ियों का खेलने का तरीका मुझसे बिल्कुल अलग हो।'

विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी अपने विजय रथ को बरकरार रखना चाहेगी भारतीय टीम

सेमीफाइनल में मलेशिया से होगी भिड़ंत



भोपाल (एजेंसी)। लगातार पांच जीत दर्ज करके शानदार फॉर्म में मौजूद भारतीय विमेंस हॉकी टीम शुक्रवार को नाथू बरखेड़ा स्थित इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के सेमीफाइनल में मलेशिया से भिड़ेगी। मौजूदा चैंपियन भारत ने 2016, 2023 और 2024 में महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। अब टीम अपने चौथे खिताब की तलाश में है, जो उसे इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम बना देगा। भोपाल संस्करण की शुरुआत से पहले, भारत और साउथ कोरिया दोनों के नाम तीन-तीन चैंपियनशिप थीं। मुख्य कोच स्योर्ड मारिन के मार्गदर्शन में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। टीम ने पांच मैचों में 15 अंक हासिल करके अंक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मौजूदा चैंपियन ने 23 गोल किए हैं और केवल चार गोल खाए हैं, जिससे उनका गोल अंतर प्लस 19 रहा है। भोपाल में भारत का अब तक का प्रदर्शन उनकी आक्रामक क्षमता और मजबूत डिफेंस को दर्शाता है। इसी शानदार खेल की बदौलत भारतीय टीम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन (एफआईएच) रैंकिंग में विश्व नंबर 4 के ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंच गई है।

दीपिका इस टूर्नामेंट की सबसे प्रभावशाली आक्रामक खिलाड़ियों में से एक बनकर उभरी हैं। उन्होंने आठ गोल के साथ स्कोरिंग चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसमें थाईलैंड और चीन के खिलाफ लगाई गई हैट्रिक भी शामिल है। हालांकि, मेजबान टीम की ताकत सिर्फ उनके टॉप स्कोरर तक ही सीमित नहीं है। लालरेमसियामी, नवनीत कौर, मुमताज खान, नेहा, साक्षी राणा और सुनेलिता टोप्पो ने भी टीम के लिए अहम योगदान दिया है।

मिडफील्ड में नवनीत ने मौके बनाने और पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में अहम भूमिका निभाई है, जबकि कप्तान सलीमा टेटे ने अपने पासिंग, मूवमेंट और नेतृत्व क्षमता से टीम को मजबूती दी है। साक्षी, सुनेलिता और नेहा के

'आप ऐसे कारनामे कर रहे हैं, जो हमारे में से ज्यादातर लोग पूरे करियर में नहीं कर पाते'

पीटरसन हुए वैभव के फैन

नई दिल्ली(एजेंसी)। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है। एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ने वाला दोहरा शतक लगाने के बाद पीटरसन ने कहा कि 15 साल का यह खिलाड़ी ऐसे कारनामे कर रहा है, जो ज्यादातर क्रिकेटर अपने पूरे करियर में भी नहीं कर पाते। सूर्यवंशी ने शानदार पावर-हिटिंग का प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 53 गेंदों में 204 रन बनाए। उनकी इस पारी में 28 छक्के और 7 चौके शामिल थे, जिसकी मदद से भारत-ए ने 7 विकेट से जीत दर्ज की और सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया। इस युवा खिलाड़ी की असाधारण पारी पर प्रतिक्रिया देते हुए पीटरसन ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी और उन्हें बेहद शानदार प्रतिभा बताया। पीटरसन ने अपने 'एक्स' पर लिखा, 'आपने करियर की शुरुआत में ही लगातार रिकॉर्ड तोड़ना वाकई कमाल है। आप ऐसे कारनामे कर रहे हैं जो हमारे में से ज्यादातर लोग अपने पूरे करियर में नहीं कर पाते। आपको और ताकत मिले, मुझे आपका सफर देखना बहुत पसंद है।' बिहार के इस युवा बल्लेबाज ने यूएई के खिलाफ रन चेज के दौरान लिस्ट-ए क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक को तहस-नहस कर दिया। उन्होंने इस फॉर्मेट में सबसे तेज शतक और दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो ऑस्ट्रेलिया के जेक फ्रेजर-मैकगर्क के रिकॉर्ड से बेहतर है।



फ्रेजर-मैकगर्क ने 2023 में तस्मानिया के खिलाफ साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए 29 गेंदों में शतक लगाया था। सूर्यवंशी ने सिर्फ 52 गेंदों में अपना पहला दोहरा शतक पूरा किया। इसके साथ ही उन्होंने लिस्ट-ए की एक पारी में किसी बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। 250 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत-ए ने सिर्फ 14.2 ओवर में 254/3 रन बनाते हुए आसानी से मैच को अपने नाम किया।

सुरेश रैनाः टी20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज

विश्व कप 2011 में निभाई थी अहम भूमिका

नई दिल्ली (एजेंसी)। टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने अपने इंटरनेशनल करियर में कई बड़े मुकाम हासिल किए। वह टी20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज रहे। इसके साथ ही उन्होंने वनडे विश्व कप 2011 में टीम इंडिया को चैंपियन बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। सुरेश रैना का जन्म 27 नवंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मुरादनगर में हुआ। रैना की क्रिकेट में दिलचस्पी अपने बड़े भाई मुकेश को क्रिकेट खेलते देखकर जागी। वह मुरादनगर के वीनस क्रिकेट क्लब में भाई के साथ



जाया करते थे। रैना ने जल्द ही इस खेल में अपना करियर बनाने की ठान ली। रैना ने क्लब स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और जल्द ही उत्तर प्रदेश की अंडर-16 टीम में जगह बना ली। अंडर-17 और अंडर-19 टीमों के लिए दमदार प्रदर्शन करने के बाद रैना ने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में अपना डेब्यू साल 2003 में किया।

घरेलू क्रिकेट में रैना ने लगातार अपनी बल्लेबाजी से काफी प्रभावित किया। 109 फर्स्ट-क्लास मैचों में रैना ने 42.15 की औसत से खेलते हुए 6,871 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 14 शतक और 45 अर्धशतक लगाए।